SHRI YASHWANT SINHA: I have still to come to my suggestions part. I will take another five-seven minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR) Then, you complete it. You complete your speech and then we will proceed to the next item on the Agenda.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: He cannot complete his speech in five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He said, 'five-seven minutes'.

SHRI YASHWANT SINHA: It might take ten minutes.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Five plus seven, twelve minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You please make up your mind. Mr. Sinha.

5.00 P. M.

SHRI YASHWANT SINHA: I have a number of suggestions to make.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Your subject is important. So, I did not want to interrupt you.

SHRI YASHWANT SINHA: That is why I thought, if you permit, I would speak the next time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ANNAJI MASODKAR): All right. He will continue next time. Now we go to the Motion of Thanks on the President's Address. Shri R. R. Sahu.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

श्री रजनी रंजन साहू (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। साथ ही, इस अवसर पर मैं भारत की महान आत्मा भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रति सम्मान भी समर्पित करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Just one minute. Up to what time will we continue this discussion?

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Upto 7 O'clock, it was agreed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Then we will not be in a position to finish it by tomorrow. I will request the House to sit up to 8 O'clock at least. Mr. Gurupadaswamy, I want the sense of the House. There are so many speakers who want to express themselves. Tomorrow we are having this matter closed. Would you agree to 8 or 8.30?

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): We can meet till 7 o'clock today and sit through lunch hour tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): But that will not help. There are several speakers.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: All right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): So, let us sit up to 8.00 o'clock today.

Yes, Mr. Sahu, you continue.

श्री जनी रंजन साहू : महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। इस अवसर पर मैं भारत की महान आत्मा भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के प्रति सम्मान समर्पित करता हूं।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा कि 21 मई का दिन एक भयंकर दुस्वप्न था। उपसभाध्यक्ष महोदय, हाल में हुए चुनाव के बाद देश में एक दुखद वातावरण बन गया है। देश सांप्रदायिकता, जातिवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के तूफान में फंस गया है। आज देश में हिंसा का वातावरण व्याप्त है और हिंसा के इस वातावरण में

पंजाब में चुनाव को रोककर हमारी सरकार ने परिपक्वता का परिचय दिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें बहुत गम्भीरता से इस बात को सोचना होगा कि आज हमारे देश के सामाजिक, राजनीति और आर्थिक ढांचे को तोड़ने की, कमजोर करने की साजिश बड़े पैमाने पर चल रही है। उत्तर में काश्मीर और पंजाब की सीमा पर देश विरोधी ताकतों द्वारा गतिविधियां तेजी से संचालित हो रही हैं। दक्षिण में 6 हजार किलोमीटर की समुद्री सीमा से भी देश विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पूर्व में आसाम तनावग्रस्त है। जिस घटना का दुखद परिणाम श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या के रूप में हुआ हैं, यह साफ जाहिर है कि तमिलनाडु में अलगाववादी तत्व बड़े पैमाने पर अपना सिर उठा चुके हैं जिसे सरकार को कुचलना है। काश्मीर और आसाम में अलगाववादी शक्तियां अपहरण की घिनौनी प्रवृत्तियों में लिप्त है और उनका लंबा सिलसिला पूर्व सरकार व०पी० सिंह की सरकार के समय से ही शुरू है। ऐसी हरकतें देश की राजनैतिक अस्थिरता के कारण हो रही हैं। दो वर्ष पूर्व जब देश में कांग्रेस के शासन था तब ऐसी शक्तियां प्रभावी नहीं थीं, लेकिन राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद से देश में अलगाववादी और आंतकवादी गतिविधियां बढ़ती चली गई। असम, पंजाब और कश्मीर के भटके हुए युवकों को हमारी सरकार मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है, जैसा कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में वर्णित है। उलफा के कुछ ऐसे युवकों को छोड़ा भी गया है, जिन पर कोई संगीन केस नहीं थे। लेकिन, ऐसे युवकों को मुख्यधारा में लाने के लिए सभी पार्टियों को मिलजुल कर प्रयास करना होगा। एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा बल्कि समस्या और बढ़ेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश जो इस देश के दो बड़े प्रांत हैं, वहां पर जातिवाद और धार्मिक उन्माद का जहर फैल चुका है। धर्म और जाति के नाम पर खेली जाने वाली राजनीति बंद होनी चाहिए। पहले से ही संकटकाग्रस्त पंजाब, कश्मीर और असम के बाद यदि यह दो राज्य भी अशांत हो गए तो देश की क्या हालत होगी? यह आसानी से समझा जा सकता है। यह दायित्व सभी पार्टियों का है कि देश का, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा न होने दें और इसका प्रयास सभी को मिलजुल कर करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया गया है, उसमें मुख्य-रूप से मैं उन नीतियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जब तक सामाजिक तनाव इस देश से समाप्त नहीं होता तब तक कोई भी घोषणा कारगर नहीं हो सकती। सामाजिक तनाव को दूर करने के लिए पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को सम्मान देना होगा। पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बारे में मंडल-कमीशन में प्रतिपादित आरक्षण नीति को सिर्फ लागू ही नहीं करना होगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उस आरक्षण का फैलाव बढ़ाना होगा। ऐसा मेरा मानना है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए जो बोर्ड की स्थापना की बात इस अभिभाषण में कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास के लिए सरकार की नीतियों का खुलासा राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए पिछली सरकार ने एक विधेयक पास किया था, उसको दृढतापूर्वक लागू करने का दायित्व इस सरकार पर है। अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा हेतु वजीफा एवम् विशेष प्रशिक्षण देने की सुविधा का विस्तार करने का दायित्व भी इस सरकार का है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक वित्तीय एवम् विकास निगम की स्थापना का जो वादा किया था उसे और सुदृढ रूप से पूर्ण किया जाए । सन् 1988 में कांग्रेस सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छोटे एवं सबसे छोटे किसान के लिए दस लाख लघु सिंचाई योजना को पूरा करने के लिए आश्वासन दिया गया था उसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाना चाहिए उसे सन् 1985–86 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के रहने के लिए चालू की गई "इंदिरा आवास योजना को चालू रखने का संकल्प भी इस अभिभाषण में दोहराया गया है, उसे पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। इसी तरह से सन् 1988–89 में चालू "कुटीर ज्योति योजना" के तहत प्रत्येक हरिजन एव आदिवासी परिवार को बिजली का एक कनेक्शन देने का वादा 5न,000 परिवार प्रतिवर्ष की दर से किया गया था, उसे चालू रखा जाए और अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए जो विकास का काम है उसे सपन्न कराया जाए । ऐसा मेरा मानना है क्योंकि तभी हमारे समाज में जो सामाजिक तनाव है उसमें कमी आएगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक अपने विचार रखे हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और उसका समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में रोजगार के लिए संसाधन जुटाने का बहुत बड़ा काम है । बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने हेतु जवाहर रोजगार योजना को श्री राजीव गांधी जी ने अपने जीवनकाल में अधिक महत्व देते हुए चलाया था, उसको दूरगामी बनाया जाना चाहिए । जब तक बेरोजगारी समाज से, इस देश से दूर नहीं होगी, तब तक हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है । अभिभाषण में फमिली प्लानिंग के बारे में भी कहा गया है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फैमिली प्लानिंग के कानून को और भी सख्त किया जाए। ...(समय की घंटी)...अभी मैं केवल पांच मिनट और लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ये सब, जो समाजिक समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान देते हुए मैं आर्थिक समस्याओं, जिनसे हम जूझ रहे है, उस ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । चुनाव के कानून में संशोधन की बात अभी कही गई, उसमें बहुत से संशोधनों की आवश्यकता है । राष्ट्रपति के अभिभाषण में कही गई बातों, उनमें अधिक खर्च करना, आर्थिक स्थिरता और स्ट्रक्चरल रिफार्म्स के बारे में वचनबद्धता हमारी सरकार की है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हू ।

आज हमारे देश में रिजर्व बैंक और आई०एम०एफ० और सोना बेचने की बातें अत्यधिक चर्चित हैं । इस संबंध में मैं रिजर्व बैंक से निवेदन करूंगा कि निर्यात को और कम्पीटीटिव बनाए और आवश्यक खर्च में कटौती करने, पूंजी निवेश में दिए जाने वाले प्रोत्साहन में कमी करने और पूंजी खाते में स्थिरता लाने के लिए कुछ कदम उठाए । यह होना ही काफी नहीं है, रिजर्व बैंक की इस देश में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज तक रिजर्व बैंक बनी बनाई लीक पर चल रही है । आज उसे इस लीक को बदलना होगा और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक, रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा जो गारण्टीज़ होता है, उसमें सुधार लाने के लिए रिजर्व बैंक को उपाय करना होगा । अब समय आ गया है जब राष्ट्रीयकृत बैंकों में स्ट्रक्चरल चेंजिंग करनी होगी । जिन उद्देश्यों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था, वे बहुत हद तक पूरे हो गए हैं लेकिन समय के मुताबिक इसमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग की जरूरत है । हम देखते हैं कि बैंकों के दो दायित्व हैं—कमर्शियल बैंकिंग और सोशियल बैंकिंग । सोशियल बैंकिंग के तहत हम गांवों में गरीबों के लिए पूंजी पहुंचाते हैं, यह हमारा सोशल आब्जेक्टिव

है राष्ट्रीयकृत बैंकों का । क्योंकि बैंकों का कारोबार बहुत बढ़ गया है इसलिए इस लक्ष्य की पूर्ति होने में कठिनाइयां आ रही हैं और जिनके लिए कार्यक्रम चलाए गए, गांव के गरीबों के लिए, वे आज उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं । बैंकों के कारोबार भी बहुत बढ़ गए हैं इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सोशियल बैंकिंग को कमर्शियल बैंकिंग से अलग कर दिया जाए और सोशियल बैंकिंग के लिए जो भी प्रतिबद्धता, जो भी कमिटमेंट सरकार का है, सोशियल आब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा उसको पूरा कराया जाए ताकि बैंक का उस तरफ से ध्यान हटकर सीधा-सीधा कमर्शियल कारोबार में लगे और उसका रिस्ट्रक्चर करना आवश्यक है । बैंकिंग सेक्टर में अनुशासनहीनता भी बढ़ती जा रही है । हमें जो आजादी मिली, उसके तहत कर्मचारी यूनियन जिन्हें मौलिक अधिकार दिया गया था ताकि वे पूर्ण क्षमता से कार्य कर सकें, व्यवस्था पर कड़ी नजर रख सकें । इसके विपरीत आज मल्टीपल्स यूनियन की वजह से बैंकों का जो उद्देश्य है पूरा नहीं हो सकता है । आज गांवों में जो बैंक खोले जाते हैं, उनमें कोई जाना नहीं चाहता है । इसलिए यह आवश्यक है कि बैंकों का रिस्ट्रक्चर किया जाए । सरकार को इस पर सोचना होगा और गभीरता से विचार करना होगा ।

उपसभाध्यक्ष(श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : प्लीज कन्क्लूड कीजिए ।

श्री रंजनी रंजन साहू : बैंकों के लिए आज कम्पीटीटिव युग है । देश में राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा विदेशी बैंक भी हैं। विदेशी बैंक के बारे में इस सदन के समक्ष मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज विदेशी बैंक की शाखाएं जो भारतवर्ष में हैं, इनमें डिपाजिट दिन दोगुना रात चौगना बढ़ता जा रहा है । लेकिन इन बैंकों की कोई सोशियल रिस्पनसिब्लिटी नहीं है । यह कहा जा सकता है कि हमारा बाइलिटरल अरेंजमेंट है, यानी हमारे बैंकों का ब्रांच विदेशों में खुलता है और विदेशी बैंकों का ब्रांच यहां खुलता है । मैं कहना चाहूंगा कि यह बैंक भी रिजर्व बैंक के गाईड लाईंस पर चलते हैं और उन्हें चाहिये कि अपने डिपोजिट के रेशो में से कुछ न कुछ परसेन्टेज प्रॉब्जक्टिव्ज को पूरा करने में इनको सहयोग दें । उपसभाध्यक्ष महोदय, आई०एम एफ० लौन और डिवैल्यूएशन के बारे में भी इस सदन में काफी चर्चाए हो चुकी हैं । 46.9 टन सोना गिरवी रखने के बारे में काफी विवाद उठ चुके हैं । इसके पूर्व भी हमारे देश में समस्यायें रही हैं जिसका जिक्र सदन में किया गया है । यह सारी समस्यायें एक साथ खड़ी हो गई हैं, इसके लिए हमें बैंक ग्राउड देखना होगा । जिस ढंग से डेफिसिट फायनेंसिंग की परम्परा चलती आ रही है, सरकार के फिजूल खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उस परिपेक्ष्य में अलग-अलग ढंग से सारी बातों को सोचना होगा । इम्पोर्ट पोलिसी जो वेस्टेड इटरेस्ट के लिए बनाई जाती है और पुन : बिगाड़ दी जाती है इन सबसे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है । खासकर पिछले दो सालों से इन बातों पर कोई विचार नहीं किया और आज वित्त मंत्रालय को बाध्य होकर एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के समय भी अनेकानेक कठिनाईयां इस देश के समक्ष आई हैं । लेकिन हमने कभी भी अपनी आत्मग्लानी बर्दाशत नहीं की और दूसरे देश के सामने घुटने नहीं टेके । हमने ग्रीन रिवौल्यूशन करके देश को खाने के पदार्थों का.... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sahu, if you go on this way, it is not going to help us. You should know that there are still a number of Members to speak.

श्री रजनी रंजन साहू : सबको आधे आधे घटा समय दिया है, हमको 10 मिनट के बाद ही आपने घंटी बजाना शुरू कर दिया ।

उपसभाध्यक्ष(श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : सुनिये तो, आज कितने लोग बोलना चाहते हैं, मालूम है ?

श्री रजनी रंजन साहू : कल भी बोलेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): So far as the time allotted to your party is concerned, only 48 minutes are thtre. There are....

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Why did you allow earlier speakers 1 hour, 30 minutes and 20 minutes, Mr. Vice-Chairman? This is not correct. You cannot....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There are still 18 Members to speak.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: That is not my responsibility. My responsibility is to speak my things.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can take your time. I have no objection but you are curtailing the time of other Members.

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Mr. Vice-Chairman, by this time I would have finished my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): All right.

श्री रजनी रंजन साहू : हमने ग्रीथन रिवेल्यूशन करके देश में खाने के पदार्थों का स्वालम्बन किया। अनेकों ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई गई जिसके द्वारा देश को संकट से उभारा गया और मुझे याद है कि तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहर लाल नेहरू की अपील पर दरभंगा महाराजा ने नेहरू जी को सोने से तोला था। आज भी यदि प्रधान मंत्री देशवासियों से अपील करें तो जो देश राजा हरिश्चन्द्र का देश है जिसने दान में अपना सब कुछ दे दिया, यह देश दानी कर्ण का देश है जिसने दान में अपने कवच कुंडल दे दिया, महात्मा बुद्ध का देश है जिसने राजपाठ त्याग कर वैराग्य ले लिया, यह महात्मा गांधी का देश है जिसने नमक आंदोलन चलाकर अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया, यह विनोबा भावे का देश है जिसने तेलगाना के आंदोलन को भूदान आंदोलन के द्वारा अहिंसक ढंग से शांत कर दिया और इस देश में बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं, जमींदारों ने अपनी-अपनी जमीनें दान दे दी। अंत: आज हमें अपने स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है । आज विदेशों के सामने जो हम झोली फैला रहे हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने यहां खर्चों में कटौती करें और अपने संसाधनों को जुटाये । इसके साथ ही साथ आज बदली हुई परिस्थिति में सरकार का भी दायित्व है कि अपनी नीति में बदलाव लाये और जिन इण्डस्ट्रीज को लिबरलाइज करने की आवश्यकता है उसे करे । पब्लिक सैक्टर के बारे में मुझे दु:ख है कि अखबारों में कभी-कभी पढ़ता हूं कि उसके शेयर्स का प्रइवेटाइजेशन किया जा रहा है । मैंने एक नोट इस संबंध में सरकार को दिया था उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार अगर उस नोट को देखे कि कैसे पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंगस में सुधार लाया जाये और उसके बारे में विचार किया जाये । बिना प्राइवेटाइजेशन लाये हुए भी सुधार लाया जा सकता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर न जाये और पब्लिक सैक्टर जो हमारे समाज की रीढ़ है उसे मजबूत करे ।

दूसरी समस्या जो सबसे ज्यादा है, उस ओर भी मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगा जितने भी ओ०जीए०ल० में, इपोर्ट लाइसेंसिज है उसे बंद कर दे ताकि बेलेंस आफ पेमेंट की कठिनाईयों से वह निबट सके । आज जिस तरह से हवाला का व्यापार विश्व में चल रहा है, बड़े-बड़े देश इस हवाला व्यापार से डिस्टेब्लाइज कर दिये हैं, इस हवाला के व्यापार को सरकार कैसे बन्द करेगी इस पर विचार करे हिन्दुस्तान में भी जो काला धन है इसके द्वारा उपार्जित किया जा रहा है इस ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं पुन: निवेदन करूंगा कि सरकार आज आर्थिक कठिनाईयों से जूझ रही है उसे पूरे व्यापक

दृष्टिकोण से एक पैकेज के रूप में देखे और उसको पैकेज के रूप में सोल्व करने का समाधान ढूंढे तभी यह देश आर्थिक कठिनाईयों से निवृत्त हो सकता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Z. A. Ahmad. You would take five minutes.

DR. Z. A. AHMAD (Uttar Pradesh): Only five minutes!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That is what is written here.

DR. Z. A. AHMAD: No. No.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The total time is hardly three hours and two minutes. And there are about 39 speakers. I am trying to find out....(*Interruption*).

DR. Z. A. AHMAD: I cannot speak in five minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): How much time do you want?

DR. Z. A. AHMAD: At least 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): 15 minutes is very long.

आप 10 मिनट लीजिए ।

डा० जैड० ए० अहमद : मैं 15 मिनट लूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपको तो कोई रोक नहीं सकता ।

डा० जैड० ए० अहमद : नहीं, आप रोक सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : लेकिन मैं आपको डिफिकल्टी बता रहा हूं कि कुल 3 घंटे और 2 मिनट का समय बाकी है और 39 स्पीकर बाकी हैं ।

एक माननीय सदस्या : आप समय एक्सटेंड कर दीजिए, इसमें क्या हर्ज है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : अच्छा, आप शुरू तो कीजिए ।

डा० जैड० ए० अहमद : मुझे बोलना तो अंग्रेजी में था लेकिन जो इकनामिक टर्म्स हमारे सामने हैं उनमें बहुत से शब्द, बहुत से फ्रेसेज अंग्रेजी के हैं जिनका हिंदी में अनुवाद मैं नहीं जानता हूं लेकिन अब अगर 5–7 मिनट के अंदर इकनामिक ऐनेलिसिस में मैं जाऊं तो यह मुश्किल है।

महोदय, आम तौर पर डिबेट में जनरल बातें कही जाती हैं, मैं भी वही कहूंगा। कुछ जनरल और कुछ पोलिटिकल बातें कहकर और इस आर्थिक संकट की ओर थोड़ा सा इशारा करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा ।

महोदय, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में हमारे देश के सामने जो राजनीतिक संकट है उसका अहसास दिलाया गया है । मैं समझता हूं कि आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन की सारी परंपराएं, सारे मूल्य और सारी उपलब्धियां खत्म होती दिखाई देती हैं । हमारा यह सपना था कि हमारा एक देश होगा, डेमोक्रेसी होगी और हम मिलकर नया हिंदुस्तान बनाएंगे । पर परिस्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है । आज देश में ऐसी ताकतें सिर उठाकर खड़ी हो गई हैं जो देश को तोड़ना चाहती हैं । महात्मा गांधी के घर में, गुजरात में आज वायलेंस की लहर चल रही है । कश्मीर उधर जा रहा है, आसाम उधर जा रहा है । तो यह जो हमने ख्वाब देखे थे, नया हिंदुस्तान बनाने के ख्वाब देखे थे, वे ख्वाब आज धूल में मिलते जा रहे हैं ।

[उपसभाध्यक्ष श्री एम० ए० बेबी पीठासीन हुए]

महोदय, यह बिल्कुल सही बात है। मैं इसे स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं। महोदय, आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और वह यह है कि अर्द्धफासिस्टवादी ताकतें आज धर्म की आड़ लेकर सिर उठा रही हैं। मैं उनको फासिस्ट ताकतें नहीं कहूंगा क्योंकि अभी वे इतनी पुख्ता नहीं हैं। लेकिन मैं उनको अर्द्ध-फासिस्ट जरूर कहूंगा। आप समझ सकते हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। मेरा इशारा बी० जे० पी० की तरफ है और उनके साथ जितने दल और ग्रुप्स जुड़े हैं उन की तरफ है। इनको कम्यूनल कहना काफी नहीं है। इनको फंडामेंटलिस्ट कहना भी काफी नहीं है। कम्यूनल है लेकिन यह कम्यूनल फेजियोलाजी आज पुरानी हो गई है। कम्यूनल और नेशनल ये फ्रेजज हैं, जुमले हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं। ये उस जमाने के जुमले हैं जबकि देश आजादी के लिए लड़ रहा था। आजादी के लिए जो लड़ते थे वे नेशनलिस्ट कहलाते थे और जो किसी एक वर्ग विशेष या समुदाय के लिए लड़ते थे वे कम्यूनल कहलाते थे। आज इनका यूज करना ठीक नहीं है। यह तो हम आजादी की लड़ाई में सारे मुल्क को यूनाइट करके, पेट्रियोटिक फोर्सेज को यूनाइट करके पेट्रियोटिक फोर्सेज को यूनाइट करके प्रजातंत्र के आधार पर, सैक्यूलरिज्म के आधार पर एक आंदोलन चलाते थे और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें जो हिंसा की आड़ लेकर, जो फूट के नारे देकर, जो नफरत का पैगाम देकर, जो दंगे करवाकर मुल्क की सारी परंपराओं या हैरिटेज को खत्म करना चाहती है उनको कम्यूनल कहना काफी नहीं है। उनके लिए दूसरा शब्द निकालना पड़ेगा और आज दुनिया की तारीख को देखकर और जो सामाजिक संघर्ष हो रहे हैं उनको देखकर उनको फासिस्ट या सेमी फासिस्ट ताकतें कहना चाहिए। इनके तौर तरीके वही हैं, इनका मोटिवेशन वही है, इनका इंसपिरेशन वही है जो किसी जमाने में हिटलर के जरिए, मुसोलिनी के जरिए यूरोप में पैदा हुआ था। यह ऐक्जजरेटेड बात नहीं है। मैं उस जमाने में जमनी में था जिस दिन हिटलर पावर में आया। मैं पूरे दौर में था जब हिटलर पावर में आया था। किस तरह से स्टेप वाई स्टेप, कदम ब कदम वही दुश्मनी, वही हेट्रेड, वही नफरत फैलाई गई। 10 साल तक करते-करते फिर एक लीडर पैदा हुआ और एक लीडर और एक नेशन हुआ। ऐग्रेसिव कम्यूनलिज्म लड़ाकू राष्ट्रवाद जो वहां था वह यहां भी पैदा हो रहा है। राष्ट्रवाद बिलकुल सही है। अपने राष्ट्र के लिए हम लड़ते हैं। लेकिन ऐग्रेसिव नेशनलिज्म एक धर्म का सहारा लेकर, एक वर्ग का सहारा लेकर अगर वह बढ़ता है तो देश में फूट पैदा करता है। तब वह राष्ट्रवाद नहीं रहता है। वह डिसरप्शन का वायस बन जाता है। फिर उस जमाने में वहां एक इटर्नल दुश्मन बना ....

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश): यह जो हिन्दू राष्ट्रवाद का नारा देते हैं।

डा० जैड० ए० अहमद: कोई हिन्दुओं की तरफ है कोई मुसलमानों की तरफ है, मैं इसमें कोई भेद नहीं करता। काश्मीर में आए या अयोध्या में आए, यह लगभग बराबर है। मैं मुकम्मल तौर पर बराबर नहीं कहता क्योंकि एक धर्म बहुत बड़ी अक्सरियत में है और दूसरा नहीं है। इसलिए इसमें क्वालिटेटिवली, गुणात्मक फर्क हो जाता है। लेकिन चीज वही है। तो अंदरूनी दुश्मन पैदा हुए हैं। अंदरूनी दुश्मन जरूरी होता है। उसने न्यूज को बनाया। यहां अंदरूनी दुश्मन मुसलमान बने। वहां अंदरूनी दुश्मन हिन्दू बनेगा। तौर तरीके आंदोलन के वही हैं— लड़ाकूपन, फूट, फिरकापरस्ती, सारी चीजें मिल बैठकर हिन्दुस्तान के अंदर एक नक्शा पैदा करती हैं जो हमारे लिए बहुत जबर्दस्त खतरनाक है। मैं उम्मीद करता था कि इस खतरे को देखकर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कुछ डाइरेक्शन मिलेगा कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा खतरा है और इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है। कम से कम कुछ डाइरेक्शन मिलना चाहिए था वह मुझे नहीं मिला, वह दिशा मुझे नहीं मिली। इसलिए इस प्रश्न पर मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण को हलका और खोखला समझता हूं।

इस वक्त जो राजनीतिक परिस्थिति है वह यह कि एक कांग्रेस की सरकार

बनी । जनता ने इसको इलेक्ट करके भेजा है । आज यह अच्छी बात है कि अपोजिशन के लोग, विरोधी पक्ष के काफी लोग यह चाहते हैं कि इस सरकार को उलटा-पुलटा न जाए, इसका तख्ता न पलटा जाए। मैं समझता हूं कि यह ठीक हो रहा है । यह इस माने में ठीक है कि रोज कोई इलेक्शन करा नहीं सकता है । रोज इलेक्शन करायेंगे तो जूते मिलेंगे । आज भी 50 फीसदी जनता वोट डालने नहीं आती है । वह ऊब चुकी है । अगर फिर इलेक्शन आप करायेंगे तो वह जूते मारेगी । इसलिए विरोधी पक्ष के लोग चाहते हैं कि इस सरकार को रहना चाहिए और हम लेफ्ट वाले, बाम पक्ष वाले अपना दबाव, अपना प्रभाव इस बात के लिए डालेंगे, अपने दूसरे सहयोगियों के साथ कि यह खिलवाड़ न किया जाए। नो कांफीडेंस मोशन लाकर इसको उलटा जा सकता है लेकिन इसको न उलटाया जाए, इसको चलने दिया जाये यह हम सब चाहते हैं । इसको कहा जायेगा, बताया जायेगा कि तुम सही दिशा में चलो। आज मुल्क के सामने राजनीतिक खतरा है इसका मुकाबला करो । जो हिन्दुस्तान के अदर सेक्यूलर फोंसज हैं उनको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए । कांग्रेस एक बड़ी सेक्यूलर फोर्स है । हालांकि कांग्रेस ने कई मसलों पर गलतियां की हैं अयोध्या के मामले में काफी गलतियां की हैं, पंजाब के मामले में काफी गलतियां की, काश्मीर के मामले में गलतियां करती आई है लेकिन फिर भी मैं आज दावे से कहता हू कि कांग्रेस जो फोर्स है वह दूसरी सेक्यूलर फोर्सेज के साथ मिलकर हिन्दुस्तान को फासिस्ट हमले से बचायेगी । बहुत बड़ा तूफान आने वाला है । दो से 80 हो गये थे और अब 80 से 120 हो गये और अगले तीन साल में आगे चले जायेंगे तो क्या हो जायेगा ..

श्री संत प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : हम तीन सौ हो जायेंगे ।

एक माननीय सदस्य : हम तीन सौ नहीं होने देंगे ।

श्री संत प्रिय गौतम : आप रोक नहीं पायेंगे ।

डा० जेड ए० अहमद: लेकिन इसका खतरा जरूर है और इसको कांग्रेस को रिलाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी जितनी और सेक्यूलर फोर्सेज है उनके साथ मिलकर उस खतरे के खिलाफ कसे जद्दोजहद किया जाय । आपको जो कम्युनल फोर्सेज बढ़ गई है इन पर काब पाने के लिए पालिटिकल एटीट्यूट लाना पड़ेगा, पालिटिकल लड़ाई लड़नी होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई नहीं । मैं आज यहां से अपील करूंगा अपने दल की तरफ से और अपने सहयोगी दलों की तरफ से कि हमें इस खतरे को देखते हुए सेक्यूलर फोर्सेज की यूनिटी को ज्यादा मजबत करना होगा । जनता दल के दो-तीन ग्रुप बन गये हैं । बड़ा अफसोस होता है जनता दल बना तो किस लिए ? आपसी लड़ाई लड़ने के लिए ? आपस में लड़ाई चल रही है लेकिन यहां साथ बैठे हुए हैं, साथ ही बातें करते हैं । मैदान में जाते हैं तो एक दूसरे से लड़ना शुरु कर देते हैं । अपने टुकड़े टुकड़े करके आपने मुल्क की हालत खराब कर दी है, काफी खराब कर दी है । आप टुकड़े-टुकड़े न होते तो एक तरफ आपका दल होता, वामपक्ष होता और कांग्रेस की अच्छी और सेक्यूलर फोर्सेज होती और ये कम्युनल फोर्सेज का मुकाबला करते । आज ये जो तीन सौ हो जाने की बात करते हैं इनको हम तीन में रेड्यूस कर देते । इसलिए मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि इसकी संभावना है और जिन्दगी का तकाजा है और जनता भी यही चाहती है कि इस लाइन को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर कामयाब करना है ।

अब मैं आर्थिक सवाल पर आता हूं । आर्थिक संकट गम्भीर है । ऐसा संकट हमने तो नहीं देखा । आज हमारा खजाना खाली है । आज हम इन्टरनेशनल भीखारी हो गये हैं । वर्ल्ड बैंक से या जहां से भी हमें पैसा मिले और जो कुछ मिले उसको लेने के लिए हम तैयार

हैं । आज हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी आर्थिक जिन्दगी के ढांचे को तोड़कर बेचने के लिए तैयार हैं, यह लज्जा की बात है और हम सब के लिए लज्जा की बात है । वर्ल्ड बैंक के सामने और इन्टरनेशनल मोनीटरी फण्ड के हाथ में अपने को बेच कर हम अपने आप को किसी तरह से जिन्दा रखना चाहते हैं । लेकिन आप जिन्दा नहीं रहेंगे । चारों तरफ से गला घोटने वाली ताकतें बैठी हुई है । आज आपको मजबूर किया जा रहा है । कंडीशनलीटीज से आपको कसा जा रहा है । मजबूर होकर आपको उनकी बातें माननी पड़ रही हैं । इसलिये सोना दिया जा रहा है । मुझे याद है, जब मैं नवजवान था तो गोल्ड ड्रेन की बात आई थी । इम्पीरिअलिज्म के जमाने की बात थी । उस वक्त अंग्रेज इम्पोर्ट करते थे । एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास साधन नहीं थे तो हम गोल्ड भेजा करते थे । आज फिर 40 साल के बाद वही हालत हो गई है । हमारी मुद्रा का जो आधार है, जो बेसिस है, उसी को बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि सोना लो और हमको खाने-पीने के लिए और जिन्दा रहने के लिए पैसा दो । यह नीति चलेगी नहीं । आज कहा जाता है कि यह सब वर्ल्ड बैंक ने ले नहीं किया । यह तो हम चाहते हैं, हम परिवर्तन चाहते हैं । इस बात का फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहीं जिक्र किया था । यह गलत बात है । आज आप दबाव में हैं, आपके सिर पर डंडा है । आप यह नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे, गुलाम हो जायेंगे । इसलिए आज हमें मजबूती के साथ अपनी नीतियों को ठीक करना है । हम साफ कहें कि हम हिन्दुस्तान के अन्दर इन्टरनेशनल कम्पनियों को कुछ नहीं देंगे । आज हालत यह है कि इन्टरनेशनल कम्पनियों के बाग दिखाये जाते हैं और कहा जाता है कि मल्टी नेशनल कम्पनियां आएंगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा । वे प्रोडक्शन बढाने के लिए नहीं आती हैं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए आती हैं । लेसेज फेयर के नाम पर जितने भी लूटेरे तबके हैं वे अपनी लूट शुरू कर देंगे । इस चीज को हमें गम्भीरता के साथ लेना पड़ेगा । जब आर्थिक ढांचे में परिवर्तन की बात आती है तो इसको हमें हल्के-फुल्के ढंग से नहीं देखना चाहिए । आज नई गुलामी हमारे ऊपर थोपी जा रही है । न्यूओ कालोनिज्म अपनी चाल चल रहा है । यूनिपोलर दुनियां अब एक पोलर हो गई है । और वह अमेरिका रह गया है । उसके अन्दर अमेरिका की रहनुमाई में, सी०आई०ए० की रहनुमाई में हमारे देश में नयी राजनैतिक चाल चलने की कोशिश की जा रही है । बल्कि हमारे आर्थिक ढांचे के टुकड़े-टुकड़े करके हमको नयी आर्थिक गुलामी में डालने की कोशिश की जा रही है ।

मैं सिर्फ चंद जुमलों में अपनी दो-चार बातें रखूंगा । इस गिरती हुई हालत को अगर संभालना है तो बजट डेफिसिट को मजबूती से कम करना होगा । क्योंकि अगर बजट डेफिसिट कम नहीं होता तो आपके पांव उखड़ जायेंगे ।

आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी खत्म करनी चाहिये और जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं उनको कहें कि आप अपने पांवों पर खड़े हों । इसको बंद करना चाहिये । इसको काफी हद तक बंद करना पड़ेगा ।

तीसरी चीज यह है कि जो सब्सिडी फर्टिलाइजर, खाद पर और खाने-पीने की चीजों पर दी जाती है उस सब्सिडी को कम नहीं करना चाहिये । हिन्दुस्तान के मेहनतकश लोग आज मंहगाई से पीड़ित हैं । अगर आप फर्टिलाइजर और खाने-पीने की चीजों पर सब्सिडी को कम करेंगे या खत्म करेंगे तो इससे इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार बड़े पैमाने पर होगा और फिर यह सरकार क्या किसी भी सरकार के लिये चलना नामुमकिन हो जायेगा । आप जब तक इन्फ्लेशन को नहीं संभालेंगे तब तक देश की हालत अच्छी नहीं हो सकती । यह जो आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे इससे इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार बड़े पैमाने पर होगा और रोजमर्रा की खाने पीने और इस्तेमाल की चीजें मंहगी हो जायेंगी इसका राजनैतिक नतीजा क्या होगा यह आप समझ सकते हैं ।... (समय की घंटी)...

जो खर्चा फौज पर किया जा रहा है यह बहुत बड़ा खर्चा है इसको फ्रीज करना चाहिये । इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिये । यह जिस लेवल पर आज है वहीं पर फ्रीज करना चाहिये ।

पांचवीं चीज यह है कि जहां तक देश के अंदर मुद्रा जमा करने का सवाल है, इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि डाइरेक्ट टैक्सेशन का जो भाग है उसको आपको ज्यादा मजबूत करना चाहिये । डाइरेक्ट टैक्स उन वर्गों पर लागू किया जाय जो मुद्रा प्रसार से जबर्दस्त फायदा उठा रहे हैं और मुनाफाखोरी करते हैं । उनके ऊपर मजबूती के साथ डाइरेक्ट टक्स लगाया जाना चाहिये और इनडाइरेक्ट टैक्स कम करने चाहियें, जिसका असर गरीब और मेहनतकश लोगों पर पड़ता है ।

आखिर में मैं एक बात कहकर बंद कर दूंगा और वह यह है कि जो बाबरी मस्जिद और रामजन्मभूमि का सवाल है, यह आज बड़ी गंभीर हालत में है । इसका हल सीधे तौर से बातचीत के द्वारा निकल आये तो अच्छा है। लेकिन मैं समझता हूं कि बात-चीत के जरिये कोई चीज निकलने वाली नहीं है । मेरी ह राय है और मैं यह समझता हूं कि स बारे में सरकार की फर्म ओपीनियन ोनी चाहिये और जो कानूनी पोजीशन ह उसकी मजबूती के साथ लागू करना चाहिये । यह समझना कि यह मामला आहिस्ता-आहिस्ता हल हो जायेगा, मैं समझता हूं कि यह मुश्किल है । इसलिये ो कुछ कीजिये अकार्डिंग टु ला कीजिये, ला के मुताबिक कीजिये । किसी दबाव में या किसी गुस्से में यह नहीं होना चाहिये । इस मामले में कानून सख्ती से लागू करना चाहिये ।

आखिर में मैं चंद बातें अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं। वे भी समझ लें, हमारे मौलाना साहब भी यहां बैठे हैं और मैं भी मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूं । ●ान कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर समझौते से काम किया जाता है । आप यह कहना चाहें कि यह जो कब्रिस्तान के इर्दगिर्द या मस्जिद के इर्दगिर्द जो जमीन है यह हमारे पर्सनल ला का हिस्सा है यह ठीक नहीं है । इसके ऊपर आपको अपना रवैया समझौते वाला रवैया करना पड़ेगा आपको हिन्दू सेंटीमेंट्स की भी इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि राम के नाम पर यह 117 सीटें जीते हैं (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : काम के नाम पर ।

डा० जेड० ए० अहमद : काम के नाम पर नहीं, दो थे, राम के नाम पर जीते हैं । इसलिए मुसलमान भाइयों को भी हिन्दू सेंटीमेंट्स का आदर करना चाहिए और ऐसा तरीकाएकार निकालना चाहिये जिससे कि कोई यह न महसूस करे कि मेरे ऊपर ज्यादती हुई है । मैं मुसलमान से भी अपील करूंगा कि अगर इसके ऊपर ज्यादा जिद की तो उसका नतीजा खराब होगा क्योंकि मौलाना साहब यहां बैठे हैं, दूसरे भाई भी हैं (व्यवधान)

श्री मौलाना असद मदनी (उत्तर प्रदेश): मौलाना साहब से कौन पूछता है, ठेकेदारों से पूछा जाता है।

श्री संघ प्रिय गौतम : उन से कह दो कि फतवे देना बन्द कर दें (व्यवधान)

डा० जेड० ए० अहमद : मैं फतवों को नहीं मानता । पालिटिक्स में धर्म के नाम पर. . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude.

DR. Z. A. AHMAD: All right.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, Dr. Nagen Saikia.

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Address of the President of India to both the Houses of Parliament is a very valuable document. The Address gives a picture of the present state of affairs in the country and the immediate steps required to be taken by the Government. But, the present Address of the Pessident does neither give a clear

picture of the state of affairs nor does it mention the immediate steps that are to be taken. Hence this Address cannot be called a mirror of present-day. India.

Sir, the President has referred, to the Punjab problem in his Address. But, he has not referred to it as to why the elections were postponed in that State after the Congress (I) formed the Government at the Centre. Elections have been postponed in the State of Punjab to September. By doing this, the Government has postponed the starting of the democratic process in that State. I am afraid, it would not be possible for the Government to hold elections in the State even in the month of september. The country will have to pay a heavy price for this mistake committed by the Government. Sir, I think that our policies concerning Punjab and Sri Lanka deserve a critical review. Even in the case of Jammu and Kashmir, the Government has not succeeded in controlling the militancy in that State.

The Address has also not mentioned anything on the steps that the Government is initiating to create an international atmosphere which is in favour of India in this regard. In Assam too, the atrocities that are being committed by the Army by killing and torturing innocent people and the molesting of women by the army personnel have not been referred to in the Address.. The Army action has only aggravated the situation in the State. The present Congress(I) Government has failed to do anything in this regard. It has not been able to find any solution to this problem so far. Sir, to combat militancy, projecting someone as an opponent or a secessionist force will prove to be detrimental. I caution the Government, the State and the country as well. Moreover, the Address makes a mention that in the elections that were held in Assam, the people of Assam have given a befitting reply to the forces of secessionism. Sir, this statement is a derogatory statement. The secessionist forces did not fight election in Assam and hence the question of giving them a befitting reply does not arise at all. Elections were fought by the regional and national parties in the State. If the Government means the AGP by it, I take strong objection to it and I demand the immediate withdrawal of this comment. At the instance of the Congress (I) such things were allowed in the election process in the State which became a great avenue for misdeeds. I want to refer to the action taken by the Election Commissioner just on the eve of the counting to mix up the ballot papers of the polling booths and do the counting and this created an atmosphere of distrust among the people.

Sir, I am glad that the honourable President has assured us to bring back the militants in Assam into the mainstream. But, at the same time, I am afraid that mishandling by the present State Government may produce the reverse results. To solve the present problem of Assam, I feel that the Central Government will have to take the initiative from Delhi itself. It has also been stated that the continuing grievances of the people will be redressed and steps will be taken for the rapid economic progress of Assam. But, I am sorry to say, the Govrenment has not got any positive attitude in this regard also. The people of Assam have been demanding a solution to the problems created by the annual floods in the State. At this moment, more than two million people have been affected very badly by the floods in the State. The whole State is reeling under water. I want to refer to the constitution of the Brahmaputra Board in 1982. The Board was constituted in 1982, about nine years ago, and the Board had submitted two master plans in 1986 to the Government of India. But, till today, the Centre has not taken the necessary steps for the implementation of these master plans. Therefore, the people of Assam have been compelled to suffer from these annual floods. If the floods cannot be controlled and if the water resources cannot be utilised properly, the people of Assam will never see an end to this problem. Without the floods being controlled the State can have no economic development as mentioned by the honourable President in his Address. For the economic development of the State, development of communications is the

first step. But, I am sorry to say, even after repeated demands by the people of the State of Assam, the Railway Ministry has not bothered to make necessary provision for the extension of the BG line up to Dibrugarh. We are talking of approachig the 21st century. But, in Assam you will be surprised to learn it takes eighteen hours to travel from Guwahati to Dibrugarh, a distance of 500 Kilometres by this MG line.

There is no proposal even to construct a bridge over the Brahmaputra near Dibrugarh. In this House, Sir, even the Union Minister of State for Home Affairs assured that the bridge would be constructed and NEC will be provided with adequate funds for the purpose. But, till today, no proposal is there with the Government and there is no mention about it also. . . (*Time bell rings*) . . .

Sir, I think from among the "Others", I am the first speaker and I think we have got more than one hour Still, I shall take only a few minutes more.

Sir, this bridge not only connects the north bank of Assam but also it will connect Arunachal Pradesh too. Moreover, from the defence point of view also, this bridge is very essential for the country. Sir, the construction work of the proposed refinery, the setting up of the propose III the reopening of Ashok Paper Mill and the necessary steps to be taken for the setting up of two Central University in the State and such other things have been waiting to get a positive treatment from the Government.

I would like to put one question to the Government: What is the annual profit of the tea industry as a whole in Assam and the proportion of the profit the tea industry invest in the State? I want a reply from the Government any time. Sir, I expect that the reply will prove that Assam is being treated as a source of raw materials and market for the finished products of such materials by the Government and non-Government agencies, both. Whenever someone from outside the State visits the State, one very comfortably praises the natural beauty or natural resources of Assam, but not a single attempt has been made by the Department of Tourism of the Government of India to harness the natural resources of Assam. The Department of Industry also has not taken any interest in setting up resource based small scale industry in the State. Such projects would help the State in many ways. But the activity of the Department of Industry in this regard is a big zero.

Sir, the Address of the President has not mentioned the most vital issue of the country, the issue of Centre-State relations, the problem of demanding sovereignty by some militant groups in the country, the problem of demanding separate States by some groups in the country. The growth and development of regional feelings in the country are some very important issues which demand immediate solution. Without reviewing the Centre-State relations and giving maximum autonomy to the states these problems cannot be solved by deploying military and para-military forces. Since 1947 the Congress Government at the Centre has always been trying to make the States weak and the Centres more and more strong. A strong Centre is no reply to this demand made by the people for more autonomy. The Resolution adopted by the State Council of Assam Gana Parishad in 1988 wanted that barring Defence, External Affairs, Coins and Communications all other subjects be transferred to the States with a view to giving them an opportunity to determine their future themselves. Only by taking such a broad and liberal outlook, the problems of secessionism and other problems of this nation could be solved. It is a matter of great concern that the Government has mortgaged a good quantity of the precious, yellow metal with foreign banks. Yesterday this issue was discussed threadbare in the House. It is for the first time in the history of our country that such an unwanted step has been taken. Along with this, the devaluation of the rupee has also been made. I am very sorry to say that in the Address there is no mention of the remedies to be taken to bring

back the pledged gold outside the country. There is no indication of taking necessary steps by the Government to recover the country from this acute financial illness. By doing this the Government has lost the trust of the people vested in them.

The hon. President has stated that the highest priority of the Government will be to keep its words. But I am afraid this Goverment is not able to keep its words. I would like to caution the Government that if the Government fails to control the prices of essential commodities it will have to face the anger of the people in no time. It has
6.00 P.M. come out in the news papers that the Government has given strong warning to hoarders and traders. But, Sir, these strong warnings cannot make even the slightest impact on the hoarders and traders of the country because of the fact that the political parties, including the ruling one are taking donations of crores and crores of rupees from these communities to run their elections. (*Time bell rings*) So until and unless the present election system is changed, there will be the prevalence of black money, and maximum corruption will be there in the public life of the country. Therefore, the Government will have to make some radical changes in the election system. But this Government does not have any proposal in this Address to do so and start working for a better future of the country.

Sir, it is very much regretted that to get the IMF loan, the Government has turned the country into a beggar in the international field. This will have a very bad effect.

Sir, the Address fails to mention the Government's wish to amend the Constitution of India to include the right to work in the list of Fundamental Rights. Only by including it as a Fundamental Right can the Government assure the people that according to the efficiency and ability of each person, necessary avenues will be open for them for their livelihood (*Time bell rings*) It will help the country in many ways. The human resources will be utilised on a planned basis and the problem of unemployment of the educated youth will also get solution to a great extent.

Lastly, Sir, once again I come to my own State. The Address does not mention about the Assam Accord. Though the Rajiv-Longowal Accord has been mentioned, the Assam Accord has not been mentioned. The Government should take necessary measures for the implementation of the Assam Accord in letter and spirit.

With so many lacunae in the Address I find it difficult to support the Motion of Thanks moved by the hon. Member. Thank you, Sir.

श्री मौलाना असद मदनी : साहब, मैं सदर साहब के खुतबे को खुशामदीद कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, खसूसन इसलिए कि कांग्रेस के मिनिस्टरों में अकलियतों के सिलसिले में जो बहुत सी बातें कही गई थीं उनमें से कुछ बातों को अहमियत देकर इस खुतबे में तजकरा किया गया है। मसलन यह कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाएगी जो इस पर एतमाद हो तरबीयत दी जाएगी और फिरकेवाराना फसादात में सही काम कर सके और कानून और इन्साफ के बरुएकार ला सके। इसी तरीके से मुकदमात और अदालतों के बारे में और इसी तरह जो लोग मजलूम हैं उनके सिलसिले में उनके किसी अज़ीज को जो मारे जाएं, किसी को मुलाजिमात देने और दूसरी चीजों का तजकरा हुआ। इसी तरह यह भी है कि इबादतगाहों के सिलसिले में 15 अगस्त, 1947 को जिस मजहब की जो भी इबादतगाह है, जिस हालत में थी उस हालत में उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई नया बिल जल्द से जल्द पार्लियमेंट में लाया जाएगा। यह बहुत ही जरूरी है और इबादतगाहों को गैर जरूरी तौर पर सियासी मकासित के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह मुल्क को बर्बाद करने के लिए इंतहाई खतरनाक किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं जिससे मुल्क में बहुत नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में

बाबरी मस्जिद का जिक्र आया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि 935 में जब बाबर शेख वायजीद की बगावत को खत्म करने के लिए सारदा और घाघरा का जो संगम है वहां गए थे अयोध्या से तकरीबन 6 मील दूर और वहां से उस बगावत को खत्म करके फिर बिहार की तरफ चले गए थे सुल्तान महमूद की बगावत को फरो करने के लिए, लेकिन बाबर कभी अयोध्या में नहीं गए। बगावत फरो करके मीर बाकी को वहां उन्होंने गवर्नर बना दिया था। मीर बांकी ने इस खुशी में खाली जमीन पर तज के बाबरी में इसका तजकरा है कि खाली जमीन पर उन्होंने मस्जिद बनाई और उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। यह बाबरी मस्जिद 935 में तामीर हुई तकरीबन 1523 में और 937 के अन्दर बाबर का इंतकाल हुआ है।

सिर्फ दो साल के बाद जादोनाद सर एलिट और डाउसन ने बाबर की मंदिर सिकनी का कोई वाक्या नकल नहीं किया। प्रोफेहर श्री राम शर्मा मुगल एम्पायर आंफ इंडिया में लिखते हैं कि हमको कोई और ऐसी शहादत नहीं मिलती कि बाबर ने किसी मंदिर को तोड़ा या किसी हिंदी को महज इसलिए ईजारसाई की हो कि वह हिंदू है। पटना यूनिवर्सिटी की तारीख के प्रोफेसर अपनी किताब मुगल किंगशिप में बाबर के मुतालिक लिखते हैं कि बाबर की तजक में हिन्दुओं के किसी मंदिर को गिराने का कोई जिक्र नहीं है और न इसका सबूत है कि उसने हिंदुओं का कत्ले आम अजहब की बिना पर किया हो। बाबर नुमाया तौर पर मजहबी ताअस्सुब और तंगदिली से बरी था। हमारे सादिक सदर डा० राजेन्द्र प्रसाद ने "इंडिया डिवाइटेड" में लिखा है कि यकम जमादुल-उला 935 को बाबर ने अपने बड़े बेटे हुमायुं को वसीयतनामे में लिखा कि, 'फरजंद खुदा का शुक्र करो कि उसने तुमको इस मुल्क की बादशाहत दी। अपने दिल से मजहबी ताअस्सुब को मिटा दो, हर मजहब वालों से इंसाफ करो, गाय की कुर्बानी छोड़ दो, तुम दिल जीत लोगे। लोग तुम्हारे एहसान से दबे रहेंगे। जो लोग हुकुमत के कानूनों की रिहायत करें, उनके मंदिरों को मुनहदिम मत करो। अदलो इंसाफ इस तरह करो कि तुम रिआया से और रिआया तुम से खुश रहे यह हवाला डा० राजेन्द्र प्रसाद साहब ने दिया है।

श्री संघ प्रिय गौतम : इस जुमले को दोबारा पढ़ दीजिए।

श्री मौलाना असद मदनी जो लोग हुकूमत के कानून की रिहायत करें ... (व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : यह एक्सेप्शन है।

श्री मौलाना असद मदनी: यह गोया डा० राजेन्द्र प्रसाद साहब ने हवाला दिया है। 14 वीं ईसवीं के आखिर में रामानंद आचार्य ने सिकंदर लोधी के जमाने में शंकर आचार्यों को मुनाजरे में शिकस्त देकर सबसे पहले राम जी की पूजा शुरू करायी। रामानंद दिग्विजय आचार्य के 12 शिष्य थे —नरहरि दरुप, देव मुरारी, कबीर दास वगैरा। नरहरि दास के शिष्य तुलसी दास हैं। 1947 की उनकी पैदाइश हैं। 126 वर्ष उनकी उम्र हुई थी और उन्होंने रामायण लिखी है। देव मुरारी ने हिंदुस्तान-भर में सबसे पहला मंदिर इलाहाबाद में बनवाया और इससे पुराना कोई राम मंदिर नहीं था। देव मुरारी के चैले रामदास ने अयोध्या में राम जन्म स्थान मंदिर, तुलसी दास के जमाने में बनवाया जो कि बाबरी मस्जिद से 50 गज के फासले पर सड़क के उस पार है जहां राम जी से मुताल्लिक तमाम मरासिम होती हैं और तमाम हिंदू मजहब वाले इसको मानते हैं। 335 साल तक बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कोई झगड़ा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुद्धिस्ट ज्योतिषी को बुलाकर मस्जिद से बाहर अहाते के अंदर मशरिक में राम जन्म स्थान और सुमाल में, उत्तर में सीता रसोई की निशानदेही करवायी। नवाबाने अवध ने मशरिक में राम चबूतरा और सुमाल में सीता जी की रसोई बनवा दी और रास्ता दिया। यह बात कि अकबर के जमाने में यह हुआ, गलत है। अवध के नवाबों ने यह करवाया। 1885 में महंत रघुनाथ दास ने चबूतरे के बारे में मुकदमा दायर किया था कि मस्जिद बनाने की इजाजत दी जाए और नक्शा दखिल किया था जिसमे मुसलमानों को मस्जिद मुस्लीम की थी

डित जज ने मुकदमा खारिज कर दिया था और इजाजत नहीं दी थी। 22 दिसंबर 1949 तक तमाम अजान, नवाज जमात इस मस्जिद में होती रही और इमाम व मुअज्जि सब मकर्रर रहे। इमाम तो अभी तक जदा है। 23 दिसंबर को सब इंस्पेक्टर लि स, रंजीत सिंह ने थाने में रिपोर्ट की कि रात कुछ लोग दीवार फांदकर मस्जिद में खिल हो गए और मूर्ति रख दी। फिजां खुद्द हुई और दफा 144 लगा दी गयी पुलिस ने दफा 145 में कुर्क कर के मुकफिकल कर दिया। फिर मस्जिद के दरवाजे भोग के नाम पर दरख्वास्त देकर अदालत से खुलवा लिए गए। सेहन में नल लगावा दिया गया और अहाते में चारों तरफ संगमरमर का फर्श लगवा दिया गया, परिक्रमा के लिए जूनूब में मंदिर बनवा दिए गए। दरजाज की दीवार में जंजीर रसद-नसब कर दिया गया वगैरा-वगैरा। अब 40 वर्ष के तमाम पुलिस और दफा 145 के बावजूद तरह-तरह के तसब्बोरात हुए कि फलां सतून है, यह नहीं है, फलां है। जो चाहा बन सकता है, लेकिन सबसे बडी बात यह है कि इस मुल्क में मुतिलम किस्म ने हुकूमतें बादशाहतें होती रही हैं अगर किसी बादशाह ने राजा ने कहीं यह किया है 10 वर्ष 50 वर्ष सौ वर्ष या 500 वर्ष पहले अब हम उन चीजों के बदले में एक दूसरे से बदला लेंगे तो इस बदले की भावना में यह मुल्क बर्बाद हो जाएगा। हमें पीछे नही जाना चाहिए, आगे की तरफ बढना चाहिए हमारा मुल्क किधर जा रहा है, हम किधर जा रहे है एक दूसरे को दश्मन बनाएं और दूसरों की वजह से कि फला ने ऐसा किया था, फलां के साथ हम ऐसा करेंगे, फलां का मजहब यह था, फलां की कौम यह थी तो पूरी कौ और मजहब के साथ मखालफत माफकत किसी एक पर, किसी की गलती यह सही, अच्छे या बुरे की जह से करना यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इस से बर्बादी आएगी। बहरहाल जो लोग होते हैं, उनके अच्छे-बुरे काम होते है। अगर कोई गलत हुई तो वह दलील नहीं देना जो अच्छी हुई है तो उनको कहिए और सबको मिलजुलकर मुल्क की भलाई के लिए आगे बढना चाहिए।

हमारा इस मामले में, हालांकि मस्जिद इबादतगाह है, अल्लाह का घर है और उसका एहजाज और इकराम होना ही चाहिए, हर मजहब की इबादतखाने की एहतराम और एहजाज होना चाहिए। लेकिन उसकी वजह से परी कौम, मुल्क, मजहब को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई धर्म मैं यह नहीं मानता कि, यह दलील देता है कि दूसरे मजहब की इबादतगाहों गिराओ तोडो, फोडो। ऐसा कोई मजहब नहीं कह सकता। अगर ऐसा कहता है तो वह मजहब नहीं है। इसलिए यह बात गलत है। हम लोगों को मिल जुलकर बर्दाशत करके, एक-दूसरे के साथ भाईचारा कायम करके, अच्छे माहौल को पैदा करने की कौशिश करनी चाहिए।

जमातल्लेमाए हिंद इस मुकदमें में सन 1949 से मद्दई है, लेकिन इसके बावजूद सन 1950 में जमातउल्लेमाए की वर्किंग कमेटी ने यह कहा कि कानून इंसाफ हुकूमत के जरिए से इसको हल किया जाय लेकिन इसको पब्लिक में बिल्कुल नहीं लाया जाए और मुद्दई होने के बावजूद भी हमने कभी इसको पब्लिक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश नहीं की। अफसोस है कि उसकी सियासत की अगराज के लिए और बुनियादी मकासिब के लिए लोगों में उस्लाम से झगडा, और पोलिटिक्स में चंद कर्सियां जीत जाएं चाहे जो हम हो मुल्क का इन चीजों से बेपरवा होकर के मुल्क में आग लागई। सैकडों फसादात किए, हजारों बेकसूरों की जानें गई। लोग कुछ नहीं जानते, मंदिर का कोई मुखालिफ नहीं। मंदिर बनाओं अपनी जमीन पर बनाओ। मंदिर बनाने के लिए दूसरे की जमीन पर बनाना, यह बात गलत है। राम जन्म स्थान मौजूद है, सब हिंदू उसको मानते है। सारी मरासिम वहां होते है। यह आज नहीं, चौदह सौ कुछ वर्ष में बना जब तुलसी दास मौजूद थे। अगर वहां मंदिर होता, टूटता तो तुलसीदास अपनी रामायण में उसका जरूर जिक्र करते कि ऐसा हुआ है। कोई ऐसी चीज नहीं है। इस तरह की चीजों करके मुल्क को बर्बाद करना और गुमराह करना, यह सब बहुत खराब बातें है।

अभी इस इलेक्शन में आर०एस०एस० के लोगों ने और बी०जे०पी० के लोगों ने मेरठ में, लखनऊ में और जगह-जगह फसादात किए, झगडे कराए। . . . व्यवधान . .

श्री संघ प्रिय गौतम : ऐसी कोई शहादत नहीं हैं ।

श्री मोलाना असद मदनी : बिल्कुल शहादत है, जनाब । बहुत शहादत हैं । बात तो यह है कि आप लोगों ने यह फैसला कर रखा है कि इंकार करते रहिए । चाहे जो कुछ हो । बड़े-बड़े कमीशनों ने इसको अपनी रिपोर्ट में माना है । सब कुछ हुआ है । मेरठ में इलेक्शन के दिनों में निगार सिनेमा से निकलते हुए मर्दों और औरतों का कत्ल किया गया और ऐसे 35 के करीब मुसलमानों के कत्ल किए गए मेरठ के अंदर । करीब 200 मुसलमानों को पुलिस के लोगों ने पकड कर हाथ-पैर तोड़ कर जेल में बंदर दिया । इस तरह से बर्बादियां होती है । इन सब चीजों को देखना चाहिए ।

इसी तरह से मुसलमानों के साथ जबर्दस्त डिसक्रिमिनेशन है, तालीम के अंदर डिसक्रिमिनेशन है, मुलाजमतों में है । आज कलास वन में एक परसेंट मुसलिम भी नहीं हैं और क्लास फोर में, जिसमे अफसरान तकरूर करते हैं, मुश्किल से तीन परसेंट होंगे हकूमत का यह फर्ज है कि इन चीजों पर गौर करे । समय की घंटी

मैं अभी खत्म करता हूं । क्या इतनी बड़ी तादाद, 18-19-20 करोड़ के करीब मुल्क में जो तादाद है, उसे इस तरीके से जाहिल बनायेंगे, इंसाफ में, कानून में, मुलाजमतों में, तालीम में, किसी भी चीज में उनको मौका नहीं देंगे ? डा० गोपाल सिंह हमारे दोस्त हैं, बड़े गवर्नर भी रहे, राज्य सभा के मेंबर भी रह होम-मिनिस्टरी ने उनको यह काम सुपुर्द किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी अकल्लियतों के मामलात में मुसलमानों की । आज तक उसको पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया है । मैं मतालवा करता हूं कि उस रिपोर्ट को बहस के लिये पेश किया जाये ताकि सूरते-हाल मालूम हो कि आज मुसलमान और अकल्लियतों की हालत क्या है और उनके साथ क्या-क्या डिसक्रिमिनेशन हो रहा है और किस तरीके से जुल्म ढाये जा रहे हैं । इसलिये इन चीजों पर गौर होना चाहिये । और एक बात सोचनी चाहिये कि हमारे मुल्क में एक दिन ऐसा था कि यहां के फूड मिनिस्टर शुरू-शुरू में गये थे और जाकर के अमरीका से गल्ला मांगा था कि मुल्क भूखा है, लाखों आदमियों के भूख से मरने का खतरा है, तो अमरीका ने कुछ अपनी शर्तें रखी थीं । वह लौट कर आये मंजूर करके और उन्होंने पंडित नेहरू से जिक्र किया कि ऐसे-ऐसे हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि चाहे आधा मुल्क भूखा मर जाये लेकिन अमरीका की गुलामी हम मंजूर नहीं करेंगे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया मिनिस्ट्री से ।फिर किदवई साहब बैठे और उन्होंने सूरतेहाल का हिम्मत से मुकाबला किया और इक्दाम उन्होंने यह किया कि मुल्क के तमाम बड़े-बड़े गल्ले के ताजिरों को बुलाया और उनको अलग-अलग बुलाकर यह कहा कि आज तुम्हें इसलिये बुलाया है कि तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनूंगा नहीं । सुनो और चले जाओ और वह यह है कि 48 घंटे के अन्दर तमाम स्टाक बाजार में आ जाय वरना तमाम स्टाक और पूरी जायदाद जब्त कर ली जायेगी । बुला-बुलाकर के दो घंटे में मुल्क के बड़े-बड़े गल्ले वालों को यह वार्निंग देकर रूख्सत कर दिया । हालत मल्क की बदल गई, स्टाक सब बाहर आ गया, तमाम कमी दूर हो गई, हालात कंट्रोल में आ गये और आहिस्ता-आहिस्ता आज मुल्क उस वक्त से लेकर आज तक मुल्क गदाई कमी में कहीं मुब्तिला नहीं हुआ । इसी तरह की मसमूई चाल आज मल्क में एक्सचेंज के बारे में ..(समय की घंटी)..लाई जा रही है और मुल्क को अमरीका का गुलाम बनाया जा रहा है और मल्क को बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है । इफराते जर और कर्जा और तरह-तरह के इक्दामात हो रहे हैं । अगर इसका हिम्मत से और पुराने जो हमारे रहनुमा थे, उस रोशनी में हल नहीं किया जायेगा, मुल्क गुलाम बना दिया गया, तो मुल्क बर्बाद हो जायेगा । आज हिन्दुस्तान की हैसियत है । हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी वाला है, कई मसायल हैं इसके और बहुत कम इसके पास दौलत है, लेकिन इसके बावजूद कभी भिखारी

[श्री मौलाना असद मजमी]

नहीं बना । संसार की इसने रहनमाई की है और आगे बढ़कर काम किया है । आज उससे हटकर के मुल्क को पीछे ले जाया जा रहा है और इस तरह की पालिसी में बुनियादी तबदीलियां, करना, यह मुल्क के मफाद के बिल्कुल खिलाफ है । हालात को कंट्रोल करने की हिम्मत पैदा करनी चाहिये और मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिये, पीछे नहीं ले जाना चाहिये . . . घंटी) . . .

मैं इन बातों के साथ आसाम के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा । आसाम में बड़ा जबदस्त सैलाब है, लाखों आदमी वहां पर बबाद है। उन चीजों की तरफ हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिये और ब्रह्मपुत्र के सैलाब पर कंट्रोल का जो प्लान है लेकिन उसको गफलत में डाला जा रहा है और उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, तवज्जो नहीं दी जा रही है, उसकी तरफ मरकजी हुकूमत को मुल्क के और मसायल से ज्यादा अहमियत देकर तवज्जो करनी चाहिये । वहां लाखों आदमी जीन, जिन्दगी और मौत, हर चीज उनकी उस पर मोकूफ है और साल भर में इतनी हानि हो जाती है कि साल भर में वह पूरा नहीं कर सकते । (समय की घंट) . . . मैं खत्म कर रहा हूं । इसलिये हुकूमत को तवज्जो दलाना चाहता हूं कि उन प्लानों को थोड़ा-थोड़ा सही, शरू करना चाहिये और दिल्ली में आबादी बढ़ती जा रही है, इसको भी जरा देखें । अगर आप दिल्ली में चारों तरफ सौ-सौ मील डबल लाइन और , इलेक्ट्री फिकेशन कर दें तो लाखों आदमी दिल्ली के बजाय करीब के दूसरे कस्बों में बसने लगेंगे और आने-जाने लगेंगे । अगर आप इस तरह से सिंगल लाइन रखेंगे और छः छः घंटे में सौ किलोमीटर गाड़ी जायेगी तो फिर सब के सब यहीं रहने को मजबूर हो जायेंगे और दिल्ली की मसीबतें बढ़ती जायेंगी । (समय की घंटी) . . . अफसोस यह है कि दिल्ली की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है कि दिल्ली पर इतना बोझ न पड़े । चारों और तवज्जो दें और सौ-सौ मील हर तरफ लाइनों को डबल करें और इलेक्ट्रिफिकेशन करायें ताकि लोग यहीं रहने पर मजबूर न हों । सौ मील के अन्दर दो, सवा दो घंट में, सुबह आयें शाम को वापिस चले जायें । इस तरह से इसका बोझ काफी कम हो सकता है । अफसोस है कि नेशनल गवनमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं कर रही है और बहुत सी लाइनें ऐसी पड़ी हुई हैं (समय की घंटी) कि सौ किलोमीटर तक छः घंटे तरफ तवज्जो नहीं कर रही है औ सी लाइनें ऐसी पड़ी हुई हैं (स सी लान एसी पड़ी हुई हैं (समय की घंटी) . . . सौ किलोमीटर तक छः घंट में पहुंचते हैं । सुबह बैठते है तो दोपहर बाद पहुंचते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम०ए०बेबी) : मजमी साहब आप खत्म करिये । प्लीज कन्कलूड ।

श्री मौलाना असद मजमी : बसमैं खत्म कर रहहूं। इसलिये मुल्क को, राजधानी को, सब चीजों को देखकर उन पर तवज्जो कीजिये और सब चीजों को हल करने की कोशिश कीजिये ।

इन अल्फाज के साथ मैं चेयर का शक्रिया अदा करते हुये अपनी बात खत्म करता हूं ।

† [شری مولانا اسعد مدنی (اتر پردیش) : صدر صاحب - میں صدر صاحب کے خطبہ کو خوش آمدید کہنے کیلئے کھڑا ہوا ہوں - خصوصاً اسلئے کہ کانگریس کے ممبروں میں اقلیتوں کے سلسلہ میں جو بہت سی باتیں کہی گئیں تھیں - ان میں سے کچھ باتوں کو اہمیت دیکر اس خطبہ میں تذکرہ کیا گیا ہے - مثلاً یہ کہ ایک ایسی فورس بنائی جائیگی جو اس پر اعتماد ہو تربیت دی جائیگی اور فرقہ وارانہ فسادات میں صحیح کام کر سکے اور قانون اور انصاف کے بروئے کار لا سکے - اسی طریقے سے مقدمات اور

[ ]. Transliteration in Arabic Script.

کے پیر بہار کی طرف چلے گئے تھے
سلطان محمود کی بغاوت کو فرو کرنے
کیلئے لیکن بابر الیودھیا نہیں گئے۔
بغاوت فرو کرکے میر باقی کو وہاں کا
انہوں نے گورنر بنادیا تھا۔ میر باقی
نے اس خوشی میں خالی زمین پر
تزک بابری میں اسکا تذکرہ ہے کہ خالی
زمین پر انہوں نے مسجد بنائی اور اسکا
نام بابری مسجد رکھا۔ یہ بابری مسجد
۹۳۵ میں تعمیر ہوئی تقریباً ۱۵۲۸ میں
اور ۹۳۷ کے اندر بابر کا انتقال ہوا۔
صرف دو سال کے بعد جارج ناراسرائیٹ
اور ڈاؤسن نے بابر کی مندر شکنی کا
کوئی واقعہ نقل نہیں کیا۔ پروفیسر شری
رام شرما "مغل ایمپائر آف انڈیا"
میں لکھتے ہیں کہ ہم کو کوئی اور ایسی
شہادت نہیں ملتی کہ بابر نے کسی مندر
کو توڑا یا کسی ہندی کو محض اسلئے
ایذا رسانی کی ہو کہ وہ ہندو ہے۔ پٹنہ
یونیورسٹی کی تاریخ کے پروفیسر اپنی
کتاب "مغل رول ان انڈیا" میں بابر کے
متعلق لکھتے ہیں کہ بابر کی تزک میں
ہندوؤں کے کسی مندر کو گرانے کا کوئی
ذکر نہیں اور نہ اسکا ثبوت ہے کہ اس
عدالتوں کے بارے میں اور اس طرح سے
لوگ مظلوم ہیں اسکے سلسلے میں آپ
کسی مخبر کو جو مارے جائیں انکو
ملازمت دینے اور دوسری چیزوں
تذکرہ ہوا۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ عبادت
گاہوں کے سلسلہ میں ۱۵ اگست
۱۹۴۷ کو جس مذہب کی جو بھی
عبادت گاہ ہے۔ جس حالت میں بھی
اس حالت میں اسکی حفاظت کی ذمہ
داری لینے کے لئے کوئی نیا بل جلد سے
جلد پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ یہ بہت
ضروری ہے اور عبادت گاہوں کو غیر
ضروری طور پر سیاسی مقاصد کیلئے
استعمال کیا جا رہا ہے اور اس طرح
ملک کو برباد کرنے کیلئے انتہائی خطرناک
قسم کے اقدامات کئے جا رہے ہیں
جس سے ملک میں بہت نقصان پہنچ
رہا ہے۔ اس سلسلہ میں بابری مسجد کا
ذکر آیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ
۹۳۵ میں جب بابر شیخ بایزید کی
بغاوت کو ختم کرنے کیلئے جونپور
اور گھاگھرا کا جو علاقہ ہے وہاں گئے
تھے الیودھیا سے تقریباً ۶ میل دور
اور وہاں سے اس بغاوت کو ختم کر

"مداخلت"...

شری شنکر پرسیئے گوتم: یہ ایکسپیشن ہے۔

شری مولانا اسعد مدنی: یہ گویا ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب نے حوالہ دیا ہے۔ ۱۴ عیسوی کے آخر میں رامانند آچاریہ نے سکندر لودھی کے زمانہ میں شنکر آچاریوں کو مناظرہ میں شکست دیکر سب سے پہلے رام جی کی پوجا شروع کرائی۔ رامانند گرو جے آچاریہ کے ۱۲ شیشیہ تھے۔ نرہری داس۔ دلو مداری کبیر داس وغیرہ۔ نرہری داس کے شیشیہ تلسی داس ہیں۔ ۱۴۹۷ کی انکی پیدائش ہے۔ ۱۲۶ ورش انکی عمر ہوئی تھی اور انہوں نے رامائن لکھی ہے۔ دلو مداری نے ہندوستان بھر میں سب سے پہلے رام مندر الہ آباد میں بنوایا اور اس سے پرانا کوئی مندر نہیں ہے رام کا۔ دلو مداری کے چیلے رام داس نے ایودھیا میں رام جنم استھان مندر تلسی داس کے زمانہ میں بنوایا جو کہ بابری مسجد سے ۵۰ گز کے فاصلہ پر [illegible] کے اس پار ہے۔ جہاں رام جی سے متعلق مراسم ہوئی ہیں اور تمام ہندو مذہب نے ہندوؤں کا قتل عام مذہب کی بنا پر کیا ہو۔ باہر نمایاں طور پر مذہبی تعصب اور تنگ دلی سے بری تھا۔ ہمارے صادق صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے "انڈیا ڈوائیڈیڈ" میں لکھا ہے کہ تیلم جاری الاولی ۹۳۵ کو بابر نے اپنے بڑے بیٹے ہمایوں کو وصیت نامہ میں لکھا کہ "فرزند خدا کا شکر کرو کہ اسنے تم کو اس ملک کی بادشاہت دی۔ اپنے دل سے مذہبی تعصب کو مٹا دو۔ ہر مذہب والوں سے انصاف کرو۔ گائے کی قربانی چھوڑ دو۔ تم دل جیت لوگے۔ لوگ تمہارے احسان سے دبے رہیں گے۔ جو لوگ حکومت کے قانون کی رعایت کریں انکے مندروں کو منہدم مت کرو۔ عدل و انصاف اس طرح کرو کہ تم رعایا سے اور رعایا تم سے خوش رہے یہ حوالہ ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب نے دیا ہے۔

شری شنکر پرسیئے گوتم: اس جملے کو دوبارہ پڑھ دیجئے

شری مولانا اسعد مدنی: جو لوگ حکومت کے قانون کی رعایت کریں۔

میں داخل ہو گئے اور مورتی رکھ دی
فضا مکدر ہوئی دفعہ ۱۴۴ لگادی گئی۔
پولیس نے دفعہ ۱۴۵ میں قرق کر کے
مقفل کر دیا۔ پھر مسجد کے دروازے
جوگی کے نام پر درخواست دیکر عدالت
سے کھلوائے گئے۔ صحن میں نل لگوا
دیا گیا۔ اور احاطے میں چاروں طرف
سنگ مرمر کا فرش لگوا دیا گیا۔ پوجا
کرنے کیلئے جنوب میں مندر بنوا دئے
گئے۔ دروازے کی دیوار میں زنجیر رسہ
نسب کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ اب
۵۰ ورش کے عام پولیس اور دفعہ
۱۴۵ کے باوجود طرح طرح کے تصورات
ہوئے کہ فلاں ستون ہے۔ یہ نہیں ہے۔
فلاں ہے۔ جو چاہا بن سکتا ہے۔ لیکن
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک
میں مختلف قسم کی حکومتیں۔ بادشاہتیں
ہوتی رہی ہیں۔ اگر کسی بادشاہ نے۔
راجا نے کہیں یہ کیا ہے۔ ۱۰ ورش۔ ۵۰
ورش۔ سو ورش یا ۵۰۰ ورش پہلے
اب ہم ان چیزوں کے بدلے میں ایک
دوسرے سے بدلا لینگے تو اس بدلے
کی بھاؤنا میں ۲ ملک برباد ہو جائینگے۔
ہمیں پیچھے نہیں جانا چاہیئے۔ آگے کی طرف

والے اسکو مانتے ہیں۔ ۳۳۵ سال
تک بابری مسجد کے متعلق میں کوئی
جھگڑا نہیں تھا۔ الہٰ آباد ہائی کورٹ
نے بدھسٹ جیوتشی کو بلا کر مسجد
سے باہر احاطے کے اندر مشرق میں
رام جنم استھان اور سیتا میں۔ اتر
میں سیتا کی رسوئی کی نشاندھی کروائی
نوابان اودھ نے مشرق میں رام
چبوترا اور سھال میں سیتا کی رسوئی
بنوادی اور راستہ دیا۔ یہ بات کہ
اکبر کے زمانہ میں یہ ہوا۔ غلط ہے۔
اودھ کے نوابوں نے یہ کروایا۔ ۱۸۸۵ میں
مہنت رگھوناتھ داس نے چبوترے کے
بارے میں مقدمہ دائر کیا تھا کہ مسجد بنانے
کی اجازت دی جائے اور نقشہ داخل کیا
تھا۔ جسمیں مسلمانوں کو مسجد تسلیم کی
تھی۔ پنڈت جج نے مقدمہ خارج کر دیا
تھا اور اجازت نہیں دی تھی۔ ۲۲ دسمبر
۱۹۴۹ تک تمام اذان۔ نماز۔ جماعت
اس مسجد میں ہوتی رہی اور امام و مؤذن
سب مقرر رہے۔ امام تو ابھی تک زندہ
ہے۔ ۲۳ دسمبر کو سب انسپکٹر پولیس
رگھبیر سنگھ نے تھانہ میں رپورٹ کی
کہ رات کو لوگ دیوار پھاند کر مسجد

مذہب کی عبادت گاہوں کو گرانا توڑنا پھوڑنا ۔ ایک کوئی مذہب نہیں کہہ سکتا۔ اگر ایسا کہتا ہے تو وہ مذہب نہیں ہے اس لئے یہ بات غلط ہے ۔ ہم لوگوں کو مل جل کر ۔ برداشت کرکے ۔ ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قایم کرکے ۔ اچھے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے جمیعۃ العلماء بھی اس مقدمے میں سنہ ۱۹۴۹ سے منعی ہے ۔ لیکن اس کے باوجود سنہ ۱۹۸۵ میں جمیعۃ العلماء کی ورکنگ کمیٹی نے یہ کہا کہ قانون انصاف حکومت کے ذریعے سے اسکو حل کیا جائے ۔ لیکن اسکو پبلک میں بالکل نہ لایا جائے اور مدعی ہونے کے باوجود بھی ہم نے کبھی اسکو پبلک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش نہیں ۔ افسوس ہے کہ اسکو سیاست کے اغراض کیلئے اور بنیادی مقاصد سے لوگوں میں اسلام سے بھٹکا اور پالیٹکس میں چند کرسیاں جیت جائیں چاہے جو ہو ملک کا ۔ ان چیزوں سے بے پرواہ ہوکر سے ملک میں آگ لگائی ۔ سینکڑوں فسادات کئے ہزاروں بے قصوروں

بڑھنا چاہئے ۔ ہمارا ملک کدھر جارہا ہے ۔ ہم کدھر جارہے ہیں ۔ ایک دوسرے کو دشمن بنائیں اور دوسروں کی وجہ سے کہ فلاں نے ایسا کیا تھا فلاں کے ساتھ ہم ایسا کریں گے ۔ فلاں کا مذہب یہ تھا ۔ فلاں کی قوم یہ تھی ۔ تو پوری کی پوری قوم اور مذہب کے ساتھ مخالفت اور مواخذت کسی ایک پر ۔ کسی کی غلطی یا صحیح اچھے یا برے کی وجہ سے کرنا یہ ملک کیلئے اچھا نہیں ہے اس سے بربادی آئیگی ۔ بہرحال جو لوگ ہوتے ہیں ۔ اُن سے اچھے بُرے کام ہوتے ہیں ۔ اگر کوئی غلط بات ہوئی تو وہ دلیل نہیں دیتا ۔ جو اچھی ہوئی ہے تو اسکو کیجئے اور سب کو مل جُل کر ملک کی بھلائی کیلئے آگے بڑھنا چاہئے ۔

ہمارا اس معاملے میں ۔ حالانکہ مسجد عبادت گاہ ہے ۔ اللہ کا گھر ہے اور اس کا احترام اکرام ہونا ہی چاہئے ہر مذہب کے عبادت خانے کی احترام اور احترام ہونا چاہئے ۔ لیکن اس کی وجہ سے پوری قوم ملک ۔ مذہب کو برباد نہیں کرنا چاہئے ۔ کوئی دھرم میں یہ نہیں مانتا کہ یہ دلیل دیتا ہے کہ دوسرے

شہادت ہے۔ جناب بہت شہادت ہے۔ بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ انکار کرتے رہیئے۔ چاہے جو کچھ ہو بڑے بڑے کمیشنوں نے اسکو اپنی رپورٹ میں مانا ہے۔ سب کچھ ہوا ہے۔ میرٹھ میں الیکشن کے دنوں میں لگاتار سینما سے نکلتے ہوئے مردوں اور عورتوں کو قتل کیا گیا۔ اور اسی ۳۵ کے قریب مسلمانوں کے قتل کئے گئے۔ میرٹھ کے اندر۔ قریب ۲۰۰ مسلمانوں کو پولیس کے لوگوں نے پکڑ کر ہاتھ پیر توڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ اس طرح زیادتیاں ہوتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیئے۔

اس طرح سے مسلمانوں نے ساتھ زبردست ڈسکریمینیشن ہے۔ تعلیم کے اندر ڈسکریمینیشن ہے۔ ملازمتوں میں ہے۔ آج کلاس ون میں ایک پرسنٹ مسلم بھی نہیں ہیں اور کلاس فور میں جمعدار افسران تعینات کرتے ہیں مشکل سے تین پرسنٹ ہونگے۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان چیزوں پر غور کرے ..... "وقت کی گھنٹی" .....

کی جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسنے مندر کا کوئی مخالف نہیں۔ مندر بناؤ اپنی زمین پر بناؤ۔ مندر بنانے کیلئے دوسرے کی زمین پر بنانا۔ یہ بات غلط ہے۔ رام جنم استھان موجود ہے۔ سب ہندو اسکو مانتے ہیں۔

ساری میراسم وہاں ہوتے ہیں۔ یہ آج ہیں جو دھا سو کچھ ورش ہوئے جب تلسی داس موجود تھے۔ اگر وہاں مندر ہوتا۔ ٹوٹتا۔ تو تلسی داس اپنی رامائن میں اسکا ضرور ذکر کرتے۔ کہ ایسا ہوا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں کر کے سماج کو برباد کرنا زور گمراہ کرنا۔ یہ سب بہت خراب باتیں ہیں۔

ابھی اس الیکشن میں آر ایس ایس کے لوگوں نے اور بی جے پی کے لوگوں نے میرٹھ میں لکھنؤ میں۔ اور جگہ جگہ فساد کرائے۔ جھگڑے کرائے۔ ..... "مداخلت" .....

شری شفیع مہریٹھ گروتم: ایسی کوئی شہادت نہیں ہے۔

شری مولانا اسعد مدنی: بالکل

اور جاکر انہوں نے فتح سنگھ کو
ملک بھیجا ہے۔ لاکھوں آدمیوں کے بھوکے
مرنے کا خطرہ ہے۔ تو امریکہ نے کچھ
شرطیں رکھی تھیں۔ وہ نہ مانے تو منظور
کیا اور انہوں نے پنڈت نہرو سے
خواہش کی کہ ایسے ایسے ہوا تو پنڈت نہرو
نے کہا کہ چاہے آدھا ملک بھوکا مر
جائے۔ لیکن امریکہ کی غلامی منظور
نہیں کریں گے اور اس کے بعد انہوں نے
استعفا دے دیا منسٹری سے۔ پھر تو وہ
صاحب بیٹھے اور انہوں نے صورت
حال کا ہمت سے مقابلہ کیا اور اقدام
انہوں نے یہ کیا کہ ملک کے تمام
بڑے بڑے غلے کے تاجروں کو بلایا اور
انکو الگ الگ بلا کر یہ کہا کہ آج تمہیں
اس لئے بلایا ہے کہ تم میری سنو میں
تمہاری سنوں گا نہیں۔ سنو اور چلے
جاؤ اور وہ یہ ہے کہ ۸ بجے گھنٹے کے اندر
تمام اسٹاک بازار میں آجائے ورنہ
تمام اسٹاک اور جائیداد ضبط کر
لی جائے گی۔ بلا بلا کر کے دو گھنٹے
میں ملک کے بڑے بڑے غلے والوں
کو یہ وارننگ دیکر رخصت کر دیا۔
حالت ملک کی مل گئی۔ اسٹاک سب

میں ابھی ختم کرتا ہوں۔ کیا اتنی
بڑی تعداد میں اشارہ انہیں ہیں
کروڑ کے قریب ملک میں جو تعداد ہے
اسے اس طریقہ سے حاصل بنائیں گے۔
انصاف میں۔ قانون میں۔ ملازمتوں
میں۔ تعلیم میں کسی بھی چیز میں انکو
موقعہ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر گوپال سنگھ
ہمارے دوست ہیں۔ بڑے گورنر بھی
رہے۔ راجیہ سبھا کے ممبر بھی رہے۔
ہوم منسٹری نے انکو یہ کام سپرد کیا
اور انہوں نے اپنی رپورٹ دی اقلیتوں
کے معاملات میں مسلمانوں کی آج
تک اسکو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا
گیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس رپورٹ
کو بحث کیلئے پیش کیا جائے تاکہ
صورت حال معلوم ہو سکے۔ کہ آج
مسلمان اور اقلیتوں کی حالت کیا ہے
اور ان کے ساتھ کیا کیا ڈسکریمینیشن
ہو رہا ہے اور کس طریقہ سے جرم
ڈھائے جا رہے ہیں۔ اس لئے ان
چیزوں پر غور کرنا چاہیئے۔ اور ایک
بات سوچنی چاہیئے کہ ہمارے ملک
میں ایک دن ایسا تھا کہ یہاں کے
فوڈ منسٹر شروع شروع میں گئے تھے

بنیادی تبدیلیاں کرنا۔ یہ ملک کے مفاد کے بالکل خلاف ہے۔ حالات کو کنٹرول کرنے کی ہمت پیدا کرنی چاہیئے اور ملک کو آگے بڑھانا چاہیئے۔ پیچھے نہیں لے جانا چاہیئے۔

"تھنکی"....

میں ان باتوں کے ساتھ آسام کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ آسام میں بڑا زبردست سیلاب ہے لاکھوں آدمی وہاں برباد ہیں۔ ان چیزوں کی طرف حکومت کو توجہ کرنی چاہیئے اور ہر ہم پتر کے سیلاب پر کنٹرول کا جو پلان ہے اسکو فوقیت میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس کو لیٹ نہیں لیا جا رہا ہے۔ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اسکی طرف مرکزی حکومت کو ملک کے اور مسائل سے زیادہ اہمیت دیکر توجہ کرنی چاہیئے۔ وہاں لاکھوں آدمی جنہیں۔ زندگی اور موت ہر چیز اسی پر موقوف ہے۔ اور سال بھر میں اتنی صفائی ہو جاتی ہے کہ سال بھر میں وہ پیدا نہیں کر سکتے....

"تھنکی"... میں ختم کر رہا ہوں۔ اسلئے حکومت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پلانوں کو تھوڑا سا تھوڑا صحیح باہر آگیا۔ تمام کمی دور ہوگئی۔ حالات کنٹرول میں آگئے۔ اور آہستہ آہستہ آج ملک اچھے وقت سے کہیں آج تک ملک خوشحالی میں کبھی مبتلا نہیں ہوا۔ اسی طرح کی معمولی چال آج ملک میں ایکسپینڈیچر کے بارے میں... وقت کی تھنکی"... چلائی جا رہی ہے اور ملک کو امریکہ کا غلام بنایا جا رہا ہے اور ملک کو بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ افراط زر اور قرضہ اور طرح طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں۔ اگر اس کا ہمت سے اور پرانے جو ہمارے رہنما تھے۔ اس روشنی میں حل نہیں کیا جائے گا۔ ملک کو جینا دیا گیا۔ تو ملک برباد ہو جائے گا۔ آج ہندوستان کی حیثیت ہے ہمارا ملک بہت بڑا ہے۔ بہت بڑی آبادی والا ہے۔ کئی مسائل ہیں اسکے اور بہت کم اس کے پاس دولت ہے۔ لیکن اسکے باوجود بھی سنگاری نہیں بنا۔ سنسار کی اس نے رہنمائی کی ہے اور آگے بڑھکر کام کیا ہے۔ آزادی سے ہٹلر نے ملک کو پیچھے لے جایا جا رہا ہے اور اس طرح کی پالیسی میں

نہیں کر رہی ہے۔ اور بہت سی لائینیں ایسی پڑی ہوئی ہیں۔ ..... "گھنٹی"... کہ سو کلومیٹر تک چھ گھنٹے میں پہونچتے ہیں۔ صبح بیٹھتے ہیں تو دوپہر بعد پہونچتے ہیں۔ .....

اپ سبھا ادھیکش (شری ایم۔ اے۔ بے بی): مدنی صاحب آپ ختم کریئے۔ پلیز کنکلوڈ۔

شری مولانا اسعد مدنی: بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اسلئے ملک کو۔ راجدھانی کو۔ سب چیزوں کو دیکھکر اس پر توجہ کیجئے۔ اور سب چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں چیئر کا تعاون ادا کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔]

شروع کرنا چاہیئے۔ اور دلی میں آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسکو بھی ذرا دیکھیں۔ اگر آپ دلی میں چاروں طرف سو سو میل ڈبل لائن اور الیکٹریفکیشن کر دیں تو لاکھوں آدمی دلی کی بجائے قریب کے دوسرے قصبوں میں بسنے لگے گے۔ اگر آپ اس طرح سے سنگل لائن رکھیں گے۔ اور چھ چھ گھنٹے میں سو کلومیٹر گاڑی جائیگی تو پھر سب کے سب یہیں رہنے کو مجبور ہو جائیں گے۔ اور دلی کی مصیبتیں بڑھتی جائیں گی۔ ... "گھنٹی" .....

افسوس یہ ہے کہ دلی کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے کہ دلی پر اتنا بڑا بوجھ نہ پڑے۔ چاروں اور توجہ دیں اور سو سو میل ہر طرف ڈبل لائن کریں۔ اور الیکٹریفکیشن کرائیں تاکہ لوگ یہیں رہنے پر مجبور نہ ہوں سو میل کے اندر دو سوا دو گھنٹہ میں۔ صبح آئیں شام کو واپس چلے جائیں اسطرح سے اسکا بوجھ کافی کم ہو سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ نیشنل گورنمنٹ اس طرف توجہ

श्री सोमपाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर आप मुझे दे रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। यह अभिभाषण सरकार की नीतियों का वक्तव्य होता है, वर्ष भर में किये जाने वाले उसके कामों का एक प्रारूप होता है, उसके चिंतन की दिशा का सूचक होता है और उसकी प्राथमिकताओं का दिग्दर्शन कराता है और सरकार के उन कार्यों का क्योंकि देश के जन-जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। देश के हर व्यक्ति और खास तौर से संसद के हर सदस्य की निगाह लगी रहती है कि राष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार क्या कहना चाहती है। इस बार के अभिभाषण में महामहिम राष्ट्रपति जी ने सबसे पहले हमारे राष्ट्र के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति, इतने बड़े नेता और युवक श्री राजीव गांधी की हत्या की चर्चा की। इस जघन्य हत्या की, इस निर्मम हत्या की इस अपराध की जितनी निंदा की जाये, उतनी कम है। मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं आपके माध्यम से, और सरकार से आग्रह करता हूं कि उनके परिवार की सुरक्षा का जितना अच्छा प्रबंध किया जा सके, सरकार करे। मुझे याद है उस दिन की उनके निधन से केवल पांच दिन पूर्व, जब मैं दिल्ली के हवाई अड्डे पालम पर अपने नेता श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के साथ कानपुर जाने के लिए गया तो जहां हमारा विशेष विमान खड़ा हुआ था उसी के साथ राजीव गांधी जी का भी विमान खड़ा हुआ था और अपने विमान के उड़ने की क्लीयरेंस मिलने से पहले हम गाड़ी के अंदर बैठकर कुछ विचार-विमर्श कर रहे थे, तभी राजीव गांधी जी की गाड़ी आई। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जानना चाहा कि यह गाड़ी किस की है और मैंने उनको सूचना दी कि शायद श्री राजीव गांधी आये हैं और वे शायद अपने विशेष विमान से कहीं जाने वाले हैं। उन्होंने उसी समय इच्छा जाहिर की कि चलें और उनसे मिला जाये, उनको विश किया जाये। मैं गाड़ी चलाकर उनके विमान तक ले गया, हम उतरे, वे आये, हंस कर हाथ मिलाया, चुनाव प्रचार आदि के संबंध में कुछ बातें कीं और फिर जोरदार ठहाका लगाया। उनके रक्तिम मुख की वह सुंदर छवि मेरे स्मृति पटल पर ऐसी अंकित हो गयी है कि बारबार रह-रह कर याद आती है। उस आदमी की हर अदा से संजीदगी टपकती थी। निश्चित रूप से राष्ट्र का ऐसा नुकसान हुआ जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में संभव नहीं।

अब माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के विषय-वस्तु पर आता हूं। अभिभाषण के अनुच्छेद-9 में सरकार ने साम्प्रदायिकता से लड़ने, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करने, अल्पसंख्यकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प दोहराया है। सरकार साधुवाद की पात्र है इस बात के लिए। उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों से निबटने के लिये एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल के गठन की बात कही है, मैं इसका स्वागत करता हूं। दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान, मृतकों के संबंधियों को रोजगार और उन्हें पुनर्वास मुहैया करने की बात, ऐसे कदम हैं जिनका सबको स्वागत करना चाहिए। राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के विषय में सरकार ने कहा है कि वह यत्न करेगी कि एक सर्वमान्य हल सब लोगों की स्वीकृति से निकाला जाये। इसमें मैं अपनी और अपने दल की तरफ से उन्हें शुभकामना देता हूं और सब प्रकार के सहयोग का वचन देता हूं और सब पक्षों से अपील करता हूं खास तौर से बी जे० पी० के अपने भाईयों से। गौतम जी यहां बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में, कि इस काम में सरकार का सहयोग द

(व्यवधान)

श्री संजय गौतम: हम तो सहयोग कर ही रहे हैं।

श्री सोमपाल: सरकार का सहयोग करें और इसे राष्ट्र हित का और राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा मानकर साम्प्रदायिक और धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव का

[श्री सोमपाल]

का वातावरण बनाये रखने के लिये जब तक ऐसा हल न निकल जाये, उस स्थल की यथा-स्थिति बनाये रखने का प्रयास करें।

महोदय, उन धार्मिक स्थलों के विषय में इस प्रकार के विवाद न खड़े हों, इसके लिए सरकार ने यह कहा है कि वह एक इस प्रकार का कानून बनाएगी जिसके अंतर्गत सभी धार्मिक स्थलों की 15 अगस्त, 1947 की स्थिति को बरकरार रखने का प्रावधान होगा। यह कदम भी स्वागत योग्य है परंतु मैं सरकार को इस संबंध में एक सावधानी बरतने के लिए जरूर कहूंगा कि यदि इस प्रकार के सभी धार्मिक स्थलों का सर्वेक्षण करा लिया जाए तो अच्छा रहेगा क्योंकि जहां कहीं अभी विवाद नहीं है, वहां इस कानून के कारण विवाद न खड़े हो जायें।

महोदय, इन सभी कदमों का स्वागत करने के साथ मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इन पर ठोस कार्यवाही की जाए। कहीं ये वायदे, वायदे ही न रह जायें। क्योंकि रैपिड ऐक्शन फोर्स बन तो जाएगी पर कहीं ऐसा न हो कि सन् 1984 के दंगों की तरह जब 48 घंटे हिंसा का नंगा नाच हुआ, लूटपाट हुई, आगजनी हुई। और जनकपुरी जहां मैं रहता हूं, वहां मैं घूमता रहा और मैंने देखा कि पुलिस खड़ी रही और उसने कोई कार्यवाही नहीं की। अगर ऐसी फोर्स बनानी है, जिस से अमल न कराना हो, तो यही बेहतर है कि इसे बनाकर हम सरकारी राजस्व पर बोझ न डालें और अगर इस पर अमल करना है तो ईमानदारी से, बिना पक्षपात के, तुरंत उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जो रैपिड ऐक्शन फोर्स बनेगी उसको त्वरित आदेश मिलना भी जरूरी है।

महोदय, अनुच्छेद 10 में महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से सरकार ने सैन्य बलों की बहुत प्रशंसा की है जो उचित भी है। पर सेना के गठन और सेना के संगठन में सैनिक अधिकारियों और दूसरे पदों और स्थानों पर की जाने वाली नियुक्तियों में बहुत सी विसंगतियां हैं जिनके कारण प्रायः सैनिकों और सैनिक अधिकारियों में असंतोष देखने में आता है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस प्रकार की विसंगतियों को यथाशीघ्र और यथासंभव दूर करने का प्रयास करें ताकि उन्हें कोई शिकायत न रहे।

महोदय, मैं पिछले अप्रैल में सिक्किम गया था, अनुमति लेकर मैं वहां इनर लाइन एरिया देखने गया था। वहां 10,000 फीट से लेकर 16,000 फीट की ऊंचाई के बीच में, पहाड़ की बर्फ से ढकी हुई चोटियों में, बर्फ के अंदर बने हुए बकरों में, आधुनिक सभ्यता और सुख-सुविधाओं से दूर, ठंड में ठिठुरते हुए सैनिक जिस प्रकार हमारी सीमा की चौकसी कर रहे हैं, उसे देखकर रोमांच हो आता है। वहां सैनिकों से बात करके मुझे पता लगा कि कुछ ऐसे स्थान हैं, जहां शहरों में तैनात अधिकारियों और सैनिकों को सीमा पर तैनात अधिकारियों और सैनिकों की तुलना में अधिक सुख-सुविधाएं और वेतन मिलते हैं। यदि ऐसी कोई विसंगति है तो मैं पुनः आग्रह करता हूं कि उसको दूर करने का प्रयास यथाशीघ्र किया जाना चाहिए।

महोदय, सेवा निवृत्त सैनिकों के बारे में अभिभाषण में कुछ बातें कही गई हैं पर वे विशेष आशाजनक नहीं हैं। सेवा निवृत्त सैनिकों की एक बहुत पुरानी और न्याय संगत मांग यह है कि समान पद के लिए समान पेंशन का प्रावधान किया जाए। मैं सरकार से पुरज़ोर अनुरोध करूंगा कि वह यह काम जल्दी से जल्दी करे। इससे हमारे राष्ट्र के इतने बड़े भाग का, जनसंख्या के इतने बड़े भाग का और हमारे देश का जो कर्तव्यनिष्ठ वर्ग माना जाता है, उसके सद्भाव को जीतने का अवसर सत्ताधारी पार्टी को मिलेगा।

महोदय, दंगों के दौरान जो अपराध होते हैं, उन्हें करने वाले अपराधियों से निपटने के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की जो बात कही गई है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं।

महोदय, अब मैं अभिभाषण के उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग पर आता हूं जो अनुच्छेद 11 से आरम्भ होता है, जिसमें राष्ट्र के सामने विद्यमान वर्तमान आर्थिक संकट की चर्चा की गई है। उसमें कहा गया है कि सामर्थ्य से अधिक खर्च देश करता रहा है और आसान तरीके, साफ्ट अप्रोच अपनाते रहा है। यह भी कहा गया है कि अब हम हालात से मजबूर हो गए हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। इस संबंध में मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि 1986 में जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक पत्र आर्थिक सुधारों और प्रायोरिटीज का सरकार के सामने प्रस्तुत किया था और आशंका लगाया था कि यदि इसी प्रकार चलन रहा तो 1990-91 तक देश का राजस्व घाटा 14 हजार से 15 हजार करोड़ रुपए हो जाएगा। उससे निपटने का काम सरकार के बूते से बाहर होगा। पता नहीं किन कारणों से उन प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया। बात दरगुजर कर दी गई और नतीजा आपके सामने है। मैं पूछना चाहता हूं कि वह आपने तरीके और साफ्ट अप्रोच का सिलसिला किसने शुरू किया। ... (व्यवधान) उन्होंने एक मुख्य सुझाव दिया था कि जो अल्पावधि के लोन हम विदेशों से लेते हैं, शार्ट टर्म लोन्स लेते हैं उसकी परंपरा को तुरन्त समाप्त किया जाए क्योंकि उनकी देयता हमारे सामने कुछ ही महीनों में खड़ी हो जाती है और उस ऋण को चुकाने के लिए दूसरा ऋण लेना पड़ता है। लेकिन वह बात भी नहीं मानी गई। अब राष्ट्रपति जी ने, सरकार ने देश का आह्वान किया कि वह कुछ कठोर निर्णय झेलने के लिए तैयार रहे। पर यह किससे कहा गया है। क्या उस 97 प्रतिशत जनता से, जिसके पास कुछ देने के लिए है ही नहीं या उन 3 प्रतिशत अमीरों से जो कि कमाई का केवल 10 प्रतिशत भी दे दें तो देश के राजस्व घाटे और हमारे भुगतान असंतुलन की समस्या को हल कर सकता है। आम आदमी फिर भी बलिदान कर सकता है, वह दे देगा जब उसके पास कुछ भी न हो। 40 प्रतिशत हमारी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है। उसके पास भरपेट भोजन नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और सिर छिपाने के लिए छत नहीं है। साल दो साल के लिए अपनी सुख सुविधाएं अगर अमीर लोग छोड़ दें तो देश का संकट हल हो सकता है।

श्रीमन्, अभिभाषण के अनुच्छेद 12 में आर्थिक स्थिरता लाने और आर्थिक विकास को गतिमान करने के लिए कुछ सुधारों की बात कही गई और उस सिलसिले में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कदम उठाए हैं। इस संबंध में माननीय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों वर्शनों के बीच जो अंतर है उसकी तरफ इंगित करना चाहता हूं। अभिभाषण के अनुच्छेद 12 में लिखा है कि "भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को अधिक प्रतियोगिता परक बनाने, पूंजी निर्गम के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहनों में कमी करने और पूंजी खाते में स्थिरता लाने के लिए पहले ही कुछ कदम उठाए हैं। हम अपने निर्यातों की प्रतियोगिता में और वृद्धि करने के उपाय करना चाहते हैं।"

इसको अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा हुआ है—

> "The Reserve Bank of India has brought about an adjustment in the exchange rate in order to strengthen competitiveness of our exports, to reduce expenditure on inessential imports...."

श्रीमन्, अवमूल्यन के इतने बड़े कदम को सिर्फ मुद्रा विनिमय की दरों में समायोजन की संज्ञा दी गई है। सरकार को शायद शर्म आ रही थी इसको अवमूल्यन कहने में और बात भी शर्म की है। अपनी झेप मिटाने के लिए कहा है कि हमने ऐडजस्टमेंट आफ ऐक्सचेंज रेट्स किया है। हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी जो विख्यात अर्थशास्त्री हैं, वे इस से भी आगे बढ़ गए। वह इसे डेप्रेशिएशन कहते हैं। 22 प्रतिशत का अवमूल्यन किया जाए केवल तीन दिन में और उसको वह

[श्री सोमपाल]

डेप्रिशियेशन कह रहे हैं। मान्यवर, मैं भी अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। छोटे-छोटे समायोजनों की जो सतत प्रक्रिया रहती है उसको डेप्रिशियेशन कहते हैं। 22 परसेंट का डैपरिशियेशन, डैपरिशियेशन नहीं अवमूल्यन माना जाता है। यह अर्थशास्त्र का बारहवीं क्लास का विद्यार्थी भी जानता है। इसके लिए डा० मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री के उपदेश या व्याख्या की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है हमारे प्रोफेसर जो मेरे टीचर भी रहे है जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था--डा० मनमोहन सिंह, शायद अपने आप को निष्णात राजनीतिज्ञ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो वह राजनीति में अर्थशास्त्र को मिलाने की कोशिश में हैं या अर्थशास्त्र में राजनीति को। पता नहीं कौन सी खिचड़ी बनायेंगे? कहीं देश का गुड़ गोबर तो नहीं कर डालने वाले हैं? अब प्रश्न आता है कि वास्तव में भुगतान असंतुलन का संकट क्या इतना बड़ा था? कितनी जरूरत थी हमें? केवल 10 हजार से 15 हजार करोड़ रुपये की जो हमारे कुल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का केवल दो परसेंट है। जैसा मैंने कहा कि यदि हम अपने देश के तीन परसेंट अमीर लोगों के अपनी आय का केवल दस परसेंट, अपनी सुख-सुविधा का दस परसेंट, छोड़ने के लिए तैयार करने में कामयाब हो जायें तो इस जरूरत की पूर्ति हो सकती है। मैं पूछता हूं इस विदेशी मुद्रा की जरूरत थी किसे? क्या 97 परसेंट लोगों को? क्या उनका काम मारूति कार, टेलीविजन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, विदेशी सैर-सपाटे के बगैर नहीं चलता? क्या उनको विदेश में अपने खाते खोलने हैं? क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने विदेश में फ्लैट और बंगले खरीदने हैं? क्या ये वही तीन परसेंट अमीर लोग नहीं हैं जिन्हें इन सब की जरूरत है। और जो पांच-सितारा जिन्दगी के आदि हैं और उसके बिना जीवन की कल्पना उनके लिए दूर की बात है? इन्हीं तीन परसेंट के लिए हमें राष्ट्र के सम्मान का सौदा करना पड़ा है अमेरिका और अमेरिका के प्रभुत्व वाली संस्था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ 10 से 15 हजार करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए हमें अपने देश की पचास हजार करोड़ की दौलत का सौदा करना पड़ा है इन देशों के साथ। अमेरिका और उसके प्रभुत्व वाली इन संस्थाओं के सामने देश को घुटने टेकने पड़े। इससे हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा गिरी है। भारत के श्रम का अवमूल्यन हुआ है। और इस एक ही कदम से भारत का आम आदमी गरीब हो गया है। हमारी मेहनत के दाम उससे ठीक आधे रह गये हैं जितने अब से दो साल पहले थे। क्या अचानक भारत का किसान और मजदूर इतना नाकारा और नपुंसक हो गया कि उसकी मजदूरी आधी रह जाए। पर कम से कम हमारी सरकार के कर्णधारों और नीति निर्धारकों ने तो आम भारतीय को यह महसूस करने पर मजबूर कर ही दिया है। इस अवमूल्यन के द्वारा।

अब सवाल यह आता है कि अवमूल्यन क्या करना पड़ा? हम यह सुधार क्यों करने जा रहे हैं? मैं इनका स्वागत करता अगर हम अपनी पहल अपने हिसाब से और अपने समय के अनुकूल इन सुधारों को, इस अवमूल्यन को करते तब तो उसका लाभ भी मिलता। जैसा कि हमने अर्थशास्त्र पुस्तकों में पढ़ा है कि यदि लगातार मुद्रास्फीति हमारे देश की अधिक दरों से बढ़ती रही हो बमुकाबले दूसरे देशों के तो हमारी मुद्रा का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है और जो अधिकृत मूल्य है वह ज्यादा रहता है। उसका समायोजन करने से हमारे निर्यात सस्ते हो जाते हैं तो उसका लाभ हमको मिलता है लेकिन वह तभी मिलता है जब अपनी चोयस और अपने अनुकूल समय पर करें। पर आपत्ति इस बात पर है कि इस मामले में डोर कहीं और से हिली है। दबाव अमेरिका से पड़ा है। अमेरिका के कब्जे वाली उसकी कठपुतली संस्थायें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में हम यह कर रहे हैं। शर्म आती है जब सुनते हैं कि 22 आदमियों की एक टीम विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हमारे विभिन्न अर्थ संबंधी मंत्रालयों में बैठकर इन सुधारों के लिए दिशा निर्देश कर रही है। अगर यह बात सही है तो बहुत शर्म की बात है। अमेरिका का कभी आदेश आता है कि भारत अणु

प्रसार रोक संधि पर हस्ताक्षर करे, कभी सुपर 301 की पाबन्दी लगाई जाती है और कार्ल हिल्स का यह कहने का हौंसला होता है कि वह भारत आकर भारत के आर्थिक ढांचे के सुधार में दखल दे। और कभी हमें कहा जाता है कि प्रतिरक्षा के व्यय मे कटौती करें आर्थिक सुधारों के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये दरवाजे खोल दें, विदेशी पूंजी निवेश और आगमन का स्वागत करें। राजस्व घाटा कम करें। अपने जन कल्याण के कार्यक्रमों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास आदि पर सरकार जो खर्चा करती है उसमें कमी करे। गरीब आदमी के उपयोग के खाद्य पदार्थों और दूसरी चीजों में जो राहत दी जाती है, उर्वरकों में जो सबसिडी दी जाती है उसमें कटौती करें, सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण करें और आगे के लिये सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश पर रोक लगा दे जिससे बहुराष्ट्रीय और एकाधिकारवादी कम्पनियों को मुनाफा कमाने के लिये खुला छोड़ दिया जाय। अमेरिका के इशारे पर यह सब कुप्रयास हो रहा है और भारत के कद को छोटा करने की कोशिश हो रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वायस आफ अमेरिका का श्रीलंका में उपस्थित होना है। इसको हमें सिगनल के रूप में लेना चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक जब बड़ा कर्जा किसी देश को देते हैं तो आर्थिक सुधारों का पैकेज उन देशों में लागू करने की शर्त लगाते हैं और आर्थिक ढांचे में मूलभूत परिवर्तन करने के लिये कहते हैं। इस बात को सारी दुनिया जानती है और इसका मेरे पास प्रमाण भी है। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 13 जुलाई, 1991 के अंक में प्रकाशित पृष्ठ 7 पर एक लेख को उद्धृत करना चाहूंगा जिसका हैडिंग है— इंडिया, स्ट्रेटेजी फार ट्रेड रिफार्मर्स। यह डाकुमेंट वर्ल्ड बैंक द्वारा बनाया गया है। यदि आप आर्थिक सुधारों को और अवमूल्यन को देखें तो शब्दशः ये आंकड़े, शतप्रतिशत हूबहू इस दस्तावेज के साथ मिलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी बुद्धि का दिवालिया निकल गया है, क्या हमारे देश की चिंतन शक्ति समाप्त हो गई है? क्या हम अपनी समस्याओं को भी नहीं समझ पाते? क्या अपने घर को ठीक करने में हम पूर्ण रूप से अक्षम हो गये? क्या हमारे सारे अर्थशास्त्री, विद्वान, प्रोफेसर, सारे समाजशास्त्री और सारे राजनैतिक नेता नाकारा हो गये हैं, बेकार हो गये हैं? अपने आप को सुपरमैन कहने वाले ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह, जो कहते हैं कि देश तो हमारे ही बल पर चल रहा है, ये सब कहां चले गये? अगर इनकी बुद्धि बेकार हो गई है तो क्यों न इनका भी एक्सपोर्ट कर दिया जाय? इनको बाहर भेज दो। लेकिन उसका भी फायदा होने वाला नहीं है क्योंकि रुपये का अवमूल्यन जो हो गया है। इनके ज्यादा दाम उठने वाले नहीं हैं। एक ही इलाज बचता है। अगर इनका इस्तेमाल नहीं होता है तो इनको डम्प कर दो, कूड़ेदान में फेंक दो। पता नहीं सरकार क्या करेगी। मैं अत्यन्त हताशा, निराशा और दुख के साथ यह टिप्पणी कर रहा हूं। यह सब जो किया जा रहा है यह गरीबों के लिये नहीं किया जा रहा है। डा. जेड.ए. अहमद चले गये, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि यह गरीबों के लिए भीख मांगी जा रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अमीरों के लिए सुख सुविधा जुटाने के लिए भीख मांगी जा रही है। उनके इशारे पर यह सब हो रहा है। यह प्रजातंत्र और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है इसका लाभ केवल 3 प्रतिशत लोगों को मिलेगा। इससे 97 प्रतिशत लोगों को तो कष्ट मिलने वाला है।

सरकार ने कीमतें कम करने का वायदा किया, सौ दिन में कम करने की बात कही। उस वक्त कांग्रेस सरकार में नहीं थी। सरकार में आने के बाद पहले ही दिन इनके वित्त मंत्री ने कहा कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं कीमतें कम कर सकूं। जो झूठ सौ दिन में खुलने वाला था वह पहले ही

[श्री सोमपाल]

दिन खुल गया । लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कलाबाजी दिखा दी । लेकिन मैं समझता हूं कि कलाबाजी कांग्रेस ने नहीं दिखाई क्योंकि कांग्रेसी अपने शरीर को इतना कष्ट नहीं देते । उन्होंने तो कलाबाजी सौ के फीगर को कराई है । वन-जीरो-जीरो से उसे जीरो-जीरो वन इतना 100 से उसको 001 कर दिया । यानी उनकी पहले ही दिन पोल खुल गई । रुपये का अवमूल्यन किया गया । कीमतें अगर घटी हैं तो रुपये की तो वह भारत का सम्मान घटा है, भारत का श्रम घटा है, भारत का चिन्तन घटा है किसानों, मजदूरों की कीमत घटी है । इस प्रकार से उन्होंने कीमतें घटाने का अपना वायदा पूरा कर तो दिया है । सोने की बिक्री की बात हो रही है । मेरे सामने अखबार रखे हैं, जिसमें उस समय के कांग्रेस प्रवक्ता और हमारे पहले जो वित्त मंत्री रह चुके हैं, माननीय प्रणव मुकर्जी और श्रीमती मारग्रेट आल्वा के बयान है । मैं पढ़ना चाहता हूं । मान्यवर, श्री मुकर्जी जी ने कहा कि "सोना बेचने का निर्णय घबराहट में लिया गया है । जो चन्द्रशेखर सरकार ने सोना बेचा है इसका बुरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगी क्योंकि सोना तभी कोई बेचता है जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता" । उन्होंने कहा कि 'यह सरकार घरेलू बाजार में पांच टन चांदी बेचना चाहती थी और देश की अचल संपत्ति और राजदूत निवास की संपत्ति तक बेच रही है । चन्द्रशेखर की यह सरकार पूरे देश को बेच रही है । इससे हमारी क्या छवि बनेगी" । जिन्होंने यह कहा वे ही आज किस मुंह से सोना बेच रहे हैं । इन्होंने संसद को गुमराह किया और कहा कि हम सोना नहीं बेचेंगे और उसके तुरन्त बाद तीन किश्तें भेज दो और उसके बाद सफाई दो कि हम इसकी डिटेल नहीं देना चाहते थे कि किस जहाज से भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं । मुझे तो अभी भी शंका है कि कल माननीय मनमोहन सिंहजी ने जो सदन में कहा कि इससे आगे रिजर्व बैंक से सोना नहीं भेजा जायेगा । इसमें भी कोई चाल है । मान्यवर, सोने का भंडार हिन्दुस्तान में केवल रिजर्व बैंक के पास ही नहीं है । सरकार के दूसरी जगहों पर भी सोने के भंडार हैं, अब वह उसमें से भेजेंगे और कहेंगे कि हमने तो वायदा किया था कि हम रिजर्व बैंक से नहीं भेजेंगे और हमने रिजर्व बैंक से नहीं भेजा । मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार संसद को विश्वास में ले और वचन दे कि सरकार किसी भी भंडार से सोना बाहर नहीं भेजेगी ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं पहले कह चुका हूं कि अंतरर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी भी उस देश को ऋण देती है जो उसके सुधारों के कार्यक्रमों को मंजूर करे और अपनी अर्थ-व्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन लाने को राजी हो । इसको एडजस्टमेंट लोन कहा जाता है । ये परिवर्तन प्रायः चार प्रकार के होते हैं ।

पहला तो यह है कि उस देश की अर्थ-व्यवस्था को विश्व की अर्थ-व्यवस्था से जोड़ने की बात कही जाती है । वर्ल्ड एकानामी से इंटीग्रेट करने की बात कही जाती है । इसको अर्थ-व्यवस्था के खुलेपन की संज्ञा दी जाती है । इसके तहत विदेशी सामान तथा विदेशी पूंजी के आगमन पर लगी सभी रोकों को समाप्त करके उनका प्रवेश आसान बनाया जाता है । माना यह जाता है कि उस सामान और सेवाओं तथा तकनीकी के निर्बाध रूप से देश में प्रवेश होने से देशी तकनीक, उत्पादकता और प्रतियोगी क्षमता बेहतर हो जाती है और देश की अर्थ-व्यवस्था कालांतर में मजबूत होती है । पर यह होने में शायद बहुत समय लगेगा लेकिन एक बात तो तुरंत हो जाती है कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का देश में आने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है । उल्लेखनीय बात है कि हमारे देश में पहले ही 600 इस प्रकार की बहु-राष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं । उनके कार्यकलाप और लेखे-जोखे को अगर देखा जाये तो एक बात सामने आती है । मैं इसमें इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इन बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा अर्जित करने के नाम पर भारी कंसेशंस हमने दे रखे हैं । पर अलम यह है कि इनमें से शीर्षस्थ 127 कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट अगर देखी जाये तो

पता लगता है कि पिछले दो सालों में, 87 और 89 के बीच में, उनमें से केवल 29 कंपनियों ने कुल 357 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की है और शेष 98 कंपनियों ने 1495 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का शुद्ध नुकसान किया है। यानी, कुल मिलाकर 1138 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इन्होंने गवाई। इन कंपनियों द्वारा कहा यह जाता है कि हम विदेशी मुद्रा अर्जित करके देंगे लेकिन क्या स्थिति है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, वैसे भी यह बात समझ से परे है कि अपनी इतनी उन्नत तकनीक को कोई विदेशी कंपनी किसी देश को दे दे। मान्यवर, यह मेरी पहली वक्तृता है, मैं पांच सात मिनट का आपसे और अनुरोध करूंगा।

इस प्रकार की उन्नत तकनीक को कोई विदेशी कंपनी किसी देश को देने वाली नहीं है जिसके आधार पर वह देश उतना ही बढ़िया सामान बनाने लगे और ताल ठोककर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुकाबला करने लायक हो जाये। कम से कम यह बात मेरी बुद्धि के परे की बात है। बहु-राष्ट्रीय कंपनियां जो मुनाफा कमाने के लिये हमारे श्रम का शोषण करने के लिये, भारत आना चाहती है उनसे हम इतनी दयानतदारी की आशा करें। अगर हम ऐसी आशा करते हैं तो यह हमारी बड़ी भारी भूल है और अब तक का हमारा प्रयोग, जैसे मैंने पहले कहा, इस संबंध में बिलकुल असफल रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुधारों का दूसरा चरण यह है कि वह सरकार की भूमिका अर्थ-व्यवस्था में कम करना चाहते हैं, अर्थात प्लानिंग की भूमिका को कम करना चाहते हैं। वर्तमान सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण और भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश में कमी करना चाहते हैं। जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि जिससे निजी उद्योग एकाधिपतियों और बहु-राष्ट्रिकों के लिये क्षेत्र खाली करने और छोड़ने की प्रक्रिया सरल हो जाये। कहा जाता है कि इससे नेचुरल मार्केट फोर्सेस के इन्टरएक्शन से कम्पीटीशन होगा, स्पर्धा बढ़ेगी और अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी। पर परिणाम यह होता है कि सारी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति उन बहुराष्ट्रीय और एकाधिकारवादियों के हाथ में आ जाती है और वस्तव में वह चाहते हैं कि हमारी निर्णायक भूमिका अर्थ व्यवस्था में हो, जिससे हम बैठ कर जो चाहें नीतियां बनवायें। यही अमरीका की इच्छा है, यहां उसके प्रभुत्व वाले अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की इच्छा है। इसी के साथ राजस्व घाटा कम करने की बात सरकार को कही जाती है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के कार्यक्रमों में किये जाने वाले खर्च में कमी, खाद्य पदार्थ, रासायनिक उर्वरक तथा अन्य मदों में दी जाने वाले सबसिडी में कमी करने की बात कही जाती है। इस प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। एक तो नीति उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिये मुनाफा कमाने का रास्ता खुल जाता है, और दूसरा यह होता है कि जनकल्याण कार्यक्रम, खाद्यान्न आदि पर दी जाने वाली सबसिडी कम होने से रोजगार के अवसर कम होते हैं और आम आदमी की वास्तविक आय कम हो जाती है। उसकी परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति घट जाती है। एक ओर मुनाफाखोरी बढ़ती है, आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण होता है दूसरी तरफ गरीब आदमी और गरीब होता है। कुल मिला कर आर्थिक विषमता और कन्सेंट्रेशन आफ इकोनोमिक पावर ज्यादा होते है। गरीबी और अमीरी का अन्तर बढ़ता है।

इन सुधारों का तीसरा चरण यह होता है कि जो लगभग दूसरे चरण से जुड़ा है कि बड़े औद्योगिक घरानों बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के विस्तार के ऊपर लगी सारी पाबन्दियों सरकार को हटानी पड़ती हैं या उनमें ढील देनी पड़ती है, मतलब यह है कि एम.आर.टी.पी. और फेरा जैसे कानूनों को या तो समाप्त किया जाता है या शिथिल किया जाता

[श्री सोनपाल]

है । लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया जाता है, जिससे सरकार क्षेत्रीय संतुलन और आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को चैक रखती है, उसके ऊपर रुकावट रखती है, सरकार के उस अधिकार को कम कर दिया जाता है। इसका परिणाम भी क्षेत्रीय असंतुलन और आर्थिक विषमता में ही होता है।

आई.एम.एफ. द्वारा निर्दिष्ट इन सुधारों का चौथा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज की तारीख में है, और जो सबसे ज्यादा चर्चित भी है, वह है मुद्रा का अवमूल्यन। अक्सर अपने देश से बहुत ज्यादा रही है, मुकाबलतन दूसरे देशों के, तो उसकी कीमत को एडजस्ट किया जाता है। इसको समायोजन कहा जाता है या डेप्रिसियेशन कहा जाता है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक चाहते हैं कि हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन बहुत बड़े प्रतिशत में करें। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो वर्ष 1990–91 में हमारी मुद्रास्फोति की दर 10 से 12 प्रतिशत रही है, जबकि विकसित देशों में यह दर औसतन 3 से 4 प्रतिशत रही है, यानि कुल अन्तर 6 प्रतिशत था और 6 प्रतिशत का अवमूल्यन इसके लिये काफी होना चाहिये था, परन्तु अवमूल्यन कितना हुआ है, 22 प्रतिशत तो अब हुआ है। यदि जनवरी, 1991 से देखें, तो 45 प्रतिशत तक अवमूल्यन हुआ है। स्थिति यह है कि भुगतान का असंतुलन, जिसको ठीक करने के लिये यह कदम हमने अफरातफरी में उठाया है, वह जैसा का का तैसा है। सोना भी बाहर भेजना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह 45 प्रतिशत का अवमूल्यन किस आधार पर किया गया हैं। कम से कम 22 प्रतिशत जो किया गया है, यह किस आधार पर किया गया, जबकि 6 प्रतिशत से काम चल जाना चाहिये था। यह किसके इशारे पर हुआ? यह विदेशी मुद्रा का संकट पैदा कैसे हुआ विदेशी मुद्रा का संकट मान्यवर हमारे विदेशी मुद्रा के सटोरे व्यापारियों और हमारे अप्रवासी भारतीय भाइयों –NRIS ने पैदा किया है। हमारे देश के ये सटोरी येन केन प्रकारेण विदेशी मुद्रा को देश से बाहर ले जाने में दिन रात लगे रहते हैं। उनके काम करने का तरीका, उनके आपरेट करने का तरीका यह रहता है कि या तो वे काले बाजार में मुद्रा खरीदते है, या निर्यात से जो अर्जित मद्रा है उसको देश में नहीं लाते विदेश मे ही जमा किये रहते हैं, जिसका कुछ इशारा कल वित्त मंत्री जी ने जो वक्तव्य सदन में दिया उसमें किया था। तीसरा काम वे यह करते हैं कि निर्यात की रकम को कम दिखाते हैं जिसको अडर इन्वाइसिंग कहा जाता है। चौथा काम काम वह करते हैं कि आयात की रकम को ज्यादा दिखाते हैं जिसको ओवर इन्व इसिंग कहा जाता है। इन चारों तरह से आपरेट करके ये लोग विदेशी मुद्रा का भडार विदेश मे जमा करते रहते हैं और रही हमारे एन0आर0आई0 भाइयों की बात तो अब उनकी देश भक्ति देख लीजिये। उन्हें हमने बहुत सारी रियायतें दे रखी है क्योंकि वे हमारे देश में विदेशी मुद्रा लायें और वे पूंजी लगाना चाहते थे। पर उन्होंने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया - अचानक एक दिन सुबह उठे और फैसला कर लिया कि इस देश में रहने का अब कोई फायदा नहीं है। यहां व्यवसाय करना बेकार है और अपने जहाज का लगर खोल दिया तथा सारी विदेशी मुद्रा जो हमारे बैंकों में जमा थी उसको निकालकर विदेश रवाना हो गया। मान्यवर, यह उन्होंने अपने चरित्र के अनुरुप ही किया, क्योंकि अगर उन्हें संघर्ष करना होता, उन्हें कष्ट झेलने होते, तो अपने देश में कोई कमी नहीं थी। परन्तु वे तो अपनी किस्मत चमकाने विदेश में गये थे और उस कार्यक्रम में क्योंकि उनको थोड़ा सा कमी लगने लगी तो सारी विदेशी मुद्रा लेकर भाग गये और आगे से वह विदेशी मुद्रा देश में भेजना भी बन्द कर दिया। 5०5०5० (समय की घंटी) मैं सिर्फ तीन-चार मिनट और लूंगा।

इस सबका नतीजा यह हुआ कि हमारी विदेशी मुद्रा का संचय घटता चला गया और अब यह दिन आ पहुंचा कि अपने करार के हिसाब से हम अपने विदेशी मुद्रा के ऋणों की अदायगी के लायक भी नहीं रहे । यह सब इसके बावजूद हुआ कि जनवरी 1991 में हमने आई० एम०एफ० से 1.8 बिलियन डालर की एक किस्त उठायी । 250 मिलियन डालर का सोना पहले बेच चुके थे। 500 मिलियन डालर अन्य देशों ने हमें समायोजन ऋण के रूप में दिया । यानी 5 महीने की अवधि में 2.6 बिलियन डालर्स की विदेशी मुद्रा का उपयोग भी हमने कर लिया और दूसरी तरफ आयातों के ऊपर कड़ी रोक भी लगाकर रखी जिससे विदेशी मुद्रा बाहर न जाय। पर सब ज्यों का त्यों बना हुआ है । हमारी यह गति क्यों हुई है? हमारी यह लगाई किसके हाथों हुई? मैं कहता हूं कि विदेशी मुद्रा के काले बाजारियों के हाथों, सटोरियों के हाथों । उन हवाला-खोरों ने हवाले के सौदे करके डालर का रेट 20 रुपये से 28 रुपये इसी साल पहुंचा दिया । भारत सरकार ने अब 18 रुपये से 25 रुपये डालर का रेट किया है रुपयों में और इस मृग मरीचिका के पीछे भागती जा रही है । लेकिन पल्ले उसके कुछ नहीं पड़ रहा है और अब कह रहे हैं कि 25 रुपये वास्तविक विनिमय दर है। अगर मान्यवर, हमें सटोरियों के इशारे पर ही चलना है और उन्होंने ही विदेशी मुद्रा का भाव तय करना है तो किसी सटोरी को वित्त मंत्री बना दीजिये यह मेरा सुझाव है। मैं यह मानता हूं कि उनके इन कुप्रयासों को, उनकी इस कुनीति को, हमें पुरस्कृत करना है तो 25 रुपये ही क्यों 28 रुपये कर दीजिये, जो हवाले का रेट है । वास्तविक तो वही है और इसमें भी संतुष्ट नहीं हों तो जब तक वे कहें तब तक बढ़ाते रहिये । इसका एक मतलब उपसभाध्यक्ष जी, मैं वह भी लेता हूं कि सरकार के बजाय सटोरियों का अंदाज लगाने का जो तरीका है वह कहीं अधिक कारगर और प्रामाणिक है । उन्हें पहले से पता था कि एक न एक दिन भारत सरकार भुगतान के असंतुलन में इस हद तक फंसेगी और हमारी उंगलियों पर नाचेगी । पर विडम्बना यह है कि हमें अपनी सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है अपने लोगों पर भरोसा नहीं है बार-बार हमें विदेशी ताकतों से अप्रवासी भारतीयों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुंह की ओर आर्थिक संकट से उबरने के लिये ताकना पड़ता है । अब एक ओर तो यह आर्थिक अनिश्चितता का वातावरण है, दूसरी ओर हमारी अल्प मत की सरकार है जिसके कारण राजनैतिक अस्थिरता देश में बनी है। सांप्रदायिक दुर्भाव चरम सीमा पर है । पंजाब, जम्मू काश्मीर, असाम आतंकवाद के शिकार हैं और एक नयी शुरुआत "लिट्टे" ने राजीव गांधी की निर्मम हत्या करके कर दी । भगवान ही जानता है कि यह नैया कब पलट जाय ।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि आई०एम० एफ० का यह नुस्खा यदि हमने बिना शर्त और सावधानी के मान लिया, तो हमारे समाज की टूट की आग में घी का काम करेगा । अवमूल्यन और राहत कटौतियों के कारण मूल्य बढ़ेंगे, खास करके आवश्यक वस्तुओं के, शहरी मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ेगा, मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त किस्तों की मांग होगी और देश में असंतोष फैलेगा । रसायनिक खाद के दाम बढ़ने के कारण किसान अपनी उपज के अधिक दाम मांगेगा । उद्योगों की निजीकरण के प्रस्तावों से छटनी की आशंका को लेकर सार्वजनिक उद्योगों के मजदूरों में असंतोष और आंदोलन होगा । आई०एम०एफ० कार्यक्रम आर्थिक विषमता को बढ़ावा देने वाला है और गरीब तबकों की टीस और ईर्ष्या बढ़ाने वाला है ।

इस सबके बावजूद, मान्यवर, भुगतान संतुलन सुधरेगा नहीं । उसके लिये तो एक ही इलाज है कि हम निर्यात बढ़ायें और आयात घटायें । पर अल्पावधि में न तो निर्यात बढ़ने वाला है और न ही आयात घटने वाला है । निर्यात हम कितना बढ़ा सकते हैं । यदि मान भी लें कि हमारा निर्यात योग्य

माल पहले के मुकाबले अवमूल्यन के बाद 15 प्रतिशत सस्ता हो गया है, तो भी विश्व बाजार में हमें अपना पूरा शेयर लेने के लिये कम से कम 25 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निर्यात करना पड़ेगा और गत वर्ष कुल मिलाकर 36 करोड़ हजार रुपये के निर्यात को देखते हुये, मुझे यह बिलकुल असंभव लगता है, सर्वथा असंभव ।

इस प्रकार लगता है कि आई०एम० एफ० का जो 2.5 बिलियन डालर का ऋण हमें मिलने वाला है, वह कुछ ही महीनों में छूमंतर हो जायेगा और हम वहीं के वहीं खड़े रह जायेंगे जहां हैं । कुल मिला कर स्थिति यह बनेगी कि निर्यात एकदम बढ़ नहीं सकता और आयात कम हो नहीं सकता । सरकार के कथनानुसार भी आयात अधिकतर तो अत्यावश्यक वस्तुओं, एसेन्शियल गुड्स के हैं या बेसिक गुड्स के । और ज्यादातर निर्यात भी ऐसे हैं, जो आयात के ऊपर आधारित है । यानी जब हम इंपोर्ट करते हैं, तभी एक्सपोर्ट कर पायेंगे । या कुछ बचे हैं, तो वह रुपी एरिया को किये जाते हैं । उनसे विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं होती । विलासिता की सामग्री के आयात में भी हम कमी नहीं कर सकते । क्योंकि रैप लाइसेंस का जो नया एक्जिम स्क्रिप बनाया है, उसका काला-बाजार में सौदा होगा और नई उदार व्यापार नीति के तहत, जिसकी सरकार रोज बड़ाई करती है, ऐसे माल की उच्च वर्ग की लोचहीन मांग के कारण इस दिशा में कोई बड़ी कमी आने वाली नहीं है । यह रास्ता भी बन्द ही समझिये ।

अब रही अदृश्य मदों की बात Invisibles उनमें भी घाटा बढ़ेगा । (समय के घंटो) अमीरों की विदेश यात्रायें राजनीतिक अस्थिरता के कारण पर्यटकों का आगमन घटेगा । यह हम पिछले वर्ष में अनुभव भी कर चुके हैं ; कि पर्यटक कम आ रहे हैं और कम से कम बढ़ोतरी तो होगी ही नहीं ।

आयातित माल पर काला-बाजारी होगी और तस्करी भी बढ़ेगी । ऋण व ब्याज की देय राशियां भी बढ़ेंगी । इस प्रकार अनुमान यह है कि भुगतान असंतुलन दस हजार करोड़ से बीस हजार करोड़ रुपये फर भी हो जायेगा और आई० एम एफ० द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि यदि 12 हजार रुपये या 15 हजार करोड़ रुपये मान भी लिया जाय, तो छः महीने के बाद दुबारा हमें उनका दरवाजा खटखटाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा । और आई०एम०एफ० कहेगा कि फिर करिये 20 प्रतिशत का अवमूल्यन अपनी मुद्रा का और हमें घुटने टेकने पड़ेंगे ।

इस तरह अर्थशास्त्र की भाषा में प्रसिद्ध ऋण भंवर में हम फंस जायेंगे, जिसको डेट ट्रैप कहा जाता है । ऐसे माहौल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों या प्रवासी भारतीय हमारे देश में पूंजी लगायें, यह सोचना भी मुझे बिलकुल तर्कसंगत नहीं लगता ।

अवमूल्यन के पक्ष में तर्क यह दिया जाता है, कि क्योंकि अवमूल्यन के कारण हमारे निर्यात सस्ते हो जायेंगे, तो उनके ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी कम हो जायेगी । पर पिछले दो वर्षों में 50 प्रतिशत अवमूल्यन तो स्वतः हो गया, जब हम इसका लाभ नहीं ले पाये तो 22 प्रतिशत से हम क्या लाभ लेंगे । इस नई व्यापार नीति और दोहरी विनिमय दर प्रणाली के कारण सट्टा बाजार जोर पकड़ेगा परिणामतः विदेशी मुद्रा पूंजीगत सामान में लगने की बजाय तुरन्त और उच्च मुनाफा देने वाली उपभोक्ता सामग्री में लग जायेगी । सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश के पूंजीगत सामान बनाने वाले उद्योगों, केपिटल गुड्स मैनुफैक्चर करने वालों को होगा । क्योंकि अप्रवासी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों यदि हमारे देश में कुछ लायेंगे, तो वह पूंजी निवेश के रूप में प्लांट और मशीनरी लायेंगी । इस मशीनरी के मुकाबले में और उनकी क्वालिटी के मुकाबले में हमारे देशी मशीनी उद्योग की मांग बुरी तरह से

प्रभावित होगी और वह मर जाने की स्थिति में आ जायेगा। इससे बेकारी बढ़ेगी, आय और घटेगी।

अवमूल्यन का इससे भी खतरनाक असर कीमतों के ऊपर पड़ने वाला है। कीमतों में चहुंमुखी बढ़ोतरी होगी। पहले तो इसलिये कि अधिकतर आयात आवश्यक वस्तुओं तथा आधारभूत वस्तुओं यानी एसेन्शियल और बेसिक गुड्स का है। आयात महंगे होने से उनके दाम तो तुरन्त बढ़ ही जायेंगे। पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों के आयात का दाम भी बढ़ेगा। और यदि बढ़े दाम उपभोक्ता पर सरकार *ने न डालने का फ़ैसला किया* तो आई० एम० एफ की शर्त का उल्लघंन होगा कि कि हमें राजस्व घाटा घटाना है। और बजट घाटा बढ़ेगा, मुद्रा-स्फीति बढ़ेगी। यदि उपभोक्ता पर मूल्य वृद्धि डाल दी जाए तो सीधे बढ़ेंगे। अब क्योंकि आयात राष्ट्रीय आय का लगभग दस प्रतिशत है तो इस 22 प्रतिशत अवमूल्यन से 2.2 प्रतिशत मूल्य स्तर तो सीधा ही बढ़ जाता है। 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे मूल्य स्तर में यह 11.2 प्रतिशत की वृद्धि आग में की तरह से हो जायेगी और फिर मूल्य दर मूल्य वृद्धि जिसको कास्केडिंग इफैक्ट कहा जाता है वह कहां पहुंचायेगा, इसकी कल्पना आप कर लीजिये दोहरी विनियम दर पद्धति जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके कारण कैपिटल गुडस का जो आयात होगा उसमें रुपये की कीमत 22 प्रतिशत के बजाय ज्यादा घटेगी। क्योंकि रैप लाइसेंस प्रीमियम पर खरीद कर माल लाना पड़ेगा। मूल्य स्तर एक अन्य कारण से भी बढ़ेगा कि हम निर्यात बढ़ाना चाहें और उस उत्साह में हमारे देश के नागरिकों के दैनिक काम आने वाले सामान, जैसे सब्जी, मांस-मछली, चीनी, चाय, काफी, चमड़ा भारी मात्रा में देश के बाहर भेजा जायेगा। और इस से हमारी आंतरिक पूर्ति (सप्लायी) कम हो जायेगी और उसके दाम बढ़ेंगे और आम आदनी की कठिनाई भी बढ़ेगी। इस सबसे बचने का केवल एक उपाय रहता है वह है अर्थ व्यवस्था को डिफ्लेट करने का यानी वित्तीय घाटा कम करने का, जन कल्याण के कार्यक्रमों के ऊपर व्यय कम करने का। सबसिडी काटने का, सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण करने और सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना बन्द करने का इस सबका नुकसान आम आदमी का होगा। आई०एम०एफ शब्दशः यही चाहता है कि हम यही करें। इसके ऊपर को देखिये इससे आम आदमी की वास्तविक आय कम होगी। रोजगार घटेगा, उसकी पर्चेजिंग पावर, क्रय शक्ति कम होगी। देशी उद्योगों द्वारा निर्मित घरेलू सामान की मांग घटेगी। घरेलू उद्योग संकट में जायेंगे और पूंजी निवेश बढ़ने का माहौल बनने के बजाय पूंजी निवेश कम होने का माहौल बनेगा और उससे और अधिक बेरोजगारी होगी। यह एक विशियस सायकल हमारे देश में होने वाला है। इसके प्रति मैं सरकार *को सचेत करना चाहता हूं।*

अब सरकार सार्वजनिक उद्योगों के निजीकरण की बात ले। एक ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश की डल्ला सीमेंट फैक्टरी का हमारे सा ने है। उसका निजीकरण करने का प्रयास सरकार ने किया और 32 या 40 मजदूरों की हत्या गोली के द्वारा हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के संगठित मजदूरों और उनकी राजनैतिक अवचेतना को देखते हुए यह कदम मुझे बिल्कुल अव्यवहारिक लगता है और हमारे देश में यह होने वाला नहीं है। अगर उन उद्योगों का निजीकरण हम करें भी तो उनको कौन लेगा? वह तो घाटे करने वाले हैं। निजी क्षेत्र वाले लोगों को तो मुनाफा चाहिए। अगर किसी तरह उनको बेच भी दिया तो उनका दाम मार्केट में क्या उठेगा? तकनीक उनके पास ऐसी पुरानी है जो हम विदेश भेज नहीं सकते हम तो खुद ही दूसरों से मांग कर रहे हैं कि बढ़िया तकनीक दें। इस प्रकार आई०एम०एफ० का यह सारा कार्यक्रम कम से कम अल्पावधि में तो अमीर का हित साधक और गरीब का विरोधी है। तीन प्रतिशत को लाभ देने के नाम पर 97 प्रतिशत लोगों का गला घोंटने वाला है। लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है और अव्यावहारिक है।

अब सवाल यह है कि इसका विकल्प क्या है? प्रायः पूछा जाता है कि

आप इसकी आलोचना तो कर रहे हैं, पर सुझाव तो दीजिए कि इसका निदान क्या है । मान्यवर, उसके लिए हमें अपनी कमर कसनी पड़ेगी एक राजनैतिक इच्छा–शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा, एक साहस जुटाना पड़ेगा, एक नई संस्कृति देश में पैदा करनी पड़ेगी इस सदन को विश्वास में लेना पड़ेगा, लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा पर आप तो विदेशों से खुलना चाहते हैं ।

मान्यवर, यह नीति तो सदा गलत रही है । जो अपने घर के लोगों से खुलकर बात नहीं करे दूसरों के सामने अपना पेट उघाड़े अपनी कमजोरी दिखाए, उनको तो मूर्ख कहा जाता है । मेरी समझ में तो यह नीति नहीं आती । यह नीति नहीं अदूरदर्शिता है, कुनीति है ।

मान्यवर, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं एक काम करना पड़ेगा कि केवल तीन प्रतिशत अमीरों से यह कहना पड़ेगा कि वे अपनी सुख–सुविधा में दो वर्ष के लिए कमी कर दें, तो देश का कल्याण हो जाए मान्यवर, यही अमीर आय०एम०एफ० के नुस्खे के सबसे बड़े वकील और पक्षधर हैं क्योंकि इन्हीं की सुख–सुविधा जुटाने के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत है । गरीब आदमी को तो विदेशी मुद्रा का कुछ करना नहीं है । लेकिन मुझे लगता है कि ये अमीर माननेवाले नहीं हैं । ये अपील से नहीं मानेंगे गरीब आदमी तो मान जाएगा अपील से क्योंकि चीन ने जब सन् 62 में हमला किया था तो मुझे याद है कि गांव की महिलाओं ने और गरीबों ने अपनी चूड़ियां, नथनियां और कान के बाले निकालकर सरकार को सोना दिया था । पर ये अमीर मानेंगे डंडे से । इसका एक तरीका है कि 12 हजार करोड़ रुपया के जो प्रत्यक्ष कर हैं उनको 60 हजार करोड़ कर दीजिए संपत्ति कर और कार्पोरेट टैक्स की वसूली को दुरूस्त कर दीजिए । वर्तमान व्यवस्था में भी बिना दरों को बढ़ाए यदि हम वसूली व्यवस्था को दुरूस्त कर दें तो 5 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष इकट्ठा कर सकते हैं (व्यवधान) अमीरों की विलास सामग्री पर रोक लगाकर आयात घटाया जाए । उच्च वर्ग के लिए संपत्ति कर और उसकी वसूली प्रक्रिया को दुरूस्त किया जाए और काले धन की अर्थव्यवस्था पर चोट की जाए । मान्यवर, यह सब करने के लिए एक प्रतिबद्धता की जरूरत है, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं और देश के नागरिकों को, विश्वास में लेने की जरूरत है । पर यहां तो सब कुछ गोपनीयता के नाम पर छुपाया जाता है और यह कहा जाता है कि यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है । सोना चुपचाप भेज दिया, अवमूल्यन चुपचाप कर दिया अपनी बात आय०एम०एफ० और अमेरिका से तो कहेंगे लेकिन अपने देशवासियों और इस देश के जिम्मेदारी सांसदों से कहने में आप गुरेज करते हैं । मान्यवर, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । आय०एम०एफ० की अपनी रिपोर्ट और आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 13 देश जिनमें ब्राजील, अर्जेंटिना, मैक्सिको, पेरू, चिली, जमैका जैर, जांबिया, मोरक्को, कीनिया, आवरीकोप्ट, फिलीपींस और थाइलैंड है । जिन्होंने अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष और वर्ल्ड बैंक से अपना कोटे से दो सौ प्रतिशत से अधिक ऋण राशियां ली इन सब देशों ने एक हां पाया देखने में आया कि घरेलू उत्पादन जी० डी० पी० की वृद्धि दर और जी०डी०पी० का अनुपात घटा, और आयात बढ़ा मुद्रास्फीति बढ़ी पूंजी का बाहर जाना बढ़ा यानी कुल मिलाकर आय०एम० एफ० का सारा नुस्खा बीमारी कम करने के बजाय बीमारी बढ़ानेवाला साबित हुआ मान्यवर, इसी क्रम में वर्तमान वित्त मंत्री का एक पुराना वक्तव्य मैं उद्धत करना चाहूंगा जो उन्होंने साउथ कमीशन के सचिव की हैसियत से 3 मार्च, 88 के क्वालालंपुर सम्मेलन के समय प्रस्ताव के रूप में पेश किया था और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से दाखिल किया गया और एडाप्ट किया गया उस प्रस्ताव की प्रति मेरे पास है । मान्यवर, डा० मनमोहन सिंह जिनका ड्राफ्ट किया हुआ यह प्रस्ताव है, जो उस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एडाप्ट किया गया है ।

"All these are desirable goals. But, if a policy and package is to be viable, it must be country-spe-

cific and free of any ideological bias. It must also be recognised that planning and carrying out structural reforms is a complex operation. Differences can and do arise in devising and agreeing on an optimum mix of polices. Grave doubts exist concerning the theoretical validiay of some of the key prescriptions now involved in the conditionalities. Their economic and social effects have in a number of cases been highly adverse. Monetary programming has frequently led to excessive idle capacity and rising unemployment".

He goes on to say:

"Financial liberalisation in conditions of inflation has led to aggravation of selective economic policy measures has aggravated the distribution of income. Insistence on import liberalisation in periods of pressure has led to aggravation of balance of payments dificits and frequently to devaluation to a degree greater than would be needed therewise Insistance of expansion of exports of primary products in many countries simultaneously has led to more than proportionate price decline and thus to decline in the value of primary exports of developing countries as a group. Insistance on free trade irrespective of country-conditions has led to many conflicts."

Sir, this is precisely what I have said in my speech.

मान्यवर, एक तरफ तो हम लोन मांगने जा रहे हैं और एक समाचार वाशिंगटन से हमारे एक अखबार में निकला है कि भारत का 12 बिलियन डालर का वर्ल्ड बैंक द्वारा दिया हुआ लोन बिना उपयोग किए हुए कई साल से पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पेनेल्टी लग रही है और वह कह रहे हैं कि जो हम आगे 600 मिलियन के और दूसरे लोन लेने वाले हैं, जितना वह लेंगे उससे ज्यादा नुकसान इसका उपयोग न करके भारत कर रहा है । इस तरह की अकुशलता, इस तरह की इनएफिसियेन्सी और दूसरी तरफ दावा करते हैं कि सुधार करेंगे, अर्थ व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे । मुझे इस सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है ।

इसी के साथ मान्यवर, वैसे तो कृषि सिंचाई और शिक्षा ऊर्जा आदि कुछ कहना चाहता था परन्तु बहुत समय ले चुका हूं, आपका पुन: धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Now, Mr. Nyodek Yonggam.

SHRI NYODEK YONGGAM (Arunachal Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks no the President's Address moved by the honourable Member, Shrimati Jayanthi Natrajan.

Sir, the new Government has been formed when the country is passing through a great a crisis and a very difficult situation. The brutal murder of our beloved leader. Shri Rajiv Gandhi, has added another dark phase in the history of our great country. The president has, in his Address, outtined elaborately the policies and programmes of the new Government, Prominent amoung them are meeting the challenges of the economic crisis, checking of price rise, curbing of terrorism and insurgency, and controlling of communalism and violence. Further, it has also promised to maintain friendly relations with our neighbouring countries and other nations as well. We all support these programmes.

During the last few days, many honourable Members of this August House have discussed the various policies and programmes laid down by the new Government before the nation at great length. I will not repeat them here now.

I appeal to the Government to see that these promises do not remain just promises on pape. The Government must be able

to deliver the goods. We will all co-operate and we will go along with the Government in its efforts to fulfil all these promises.

Bill, Sir, as one of the members from the north-eastern region, I am sorry to say that in his Address the President has not said much about north-eastern States of India, except some casual reference of terrorist and insurgency activities by certain group of people in Assam, Nagaland and in Manipur in paras 5 and 8, respectively.

Sir, today some States of north-east are burning like those of Punjab and Jammu and Kashmir. Therefore, I appeal to the New Government to have positive approach to the burning problems of north east and bring lasting peace in the region immediately.

Sir, of our 44 years of independence, north-eastern States still remain backward in comparison to other parts of the country. Why so, Sir? Whoever comes to power in Centre pays less attention towards north-eastern States.

Sir, the north-eastern States have got abundant natural resources. We have coal, oil, timber and tea. These resources have not been properly utilised as per the requirements of the local people there.

Sir, due to industrial backwardness, unprecedented growth of unemployment, non-availability of adequate technical institutions, poor road communications, inadequate railways and air services in the region, the youth of these States today are taking a negative view of Delhi, though we have been trying our best to bring them into the mainstream of national life. Gross negligence of the Central Governments in the past, terrorism and insurgencies have taken place in Tripura by T.N.V., M.N.F. in Mizodam, N.S.C.N; in Nagaland, P.L.O. in Manipur and ULFA in Assam.

Sir, I put forward a humble suggestion to the new Government to bring lasting peace in terrorist infected areas of these north-eastern States and to create a new Department like 'North East Affairs' in the Ministry of Home Affairs.

I hope that the Government will take necessary steps to bring peace in north eastern region and top priority will be given for industrialisation of the region.

Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Shri Ramachandran Pillai. This is also his maiden speech.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Yes, it is my maiden speech. I may be allowed to speak from the front.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please come.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Thank you.

Sir, the Presidential Address mentioned about the growing economic crisis in our country. We are facing an unprecedented crisis. This has imposed great burden and unheard miseries on our people. Sir, the crisis is not confined to the economic sphere alone. We are facing an all-round crisis. We see crisis in every sphere of our life. The unity of the country is in danger. The freedom of the country is in danger. The unity of the people is being attacked by the communal monster. Our federal, democratic polity is being attached. The parliamentary, democratic, system and the Centre-State relations are being undermined. Not only this. The whole law and order situation is deteriorating. Terror and violence are reigning in our country Sir, I am disappointed by the speech by the President. That shows that the Government is not realising the gravity of the whole situation. They are not offering any remedies for these maladies. Some of the remedies they offer fall far short of the needs. Some of the remedies they offer are worse than the maladies. Sir, who is responsible for this state of affairs? The Government and

the Congress(I) Party, it seems, they want to put the blame on the Natioial Front Government. The National Front Government was there hardly for 11 months. How can the blame be put on them?

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, it is better the Minister listens to him than to any other Member.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Sir, I don't think that these arguments will satisfy any. Actually the present crisis is the creation of the capitalist path of development and the wrong policies of the Congress(I) Party. My question is: Does the Congress(I) Party realise this? And will they make any redical changes in their policies? Now, in the name of changing policies, they are taking some steps This will aggravate the situation. They are allowing private sector to capture the public sector. What all positive aspect was there in the past, they are trying to throw it away. They are allowing the monopolists to capture the nationalised banks. They are inviting the multinationals to control our economy. They are soccumbing to the pressures of the IMF. So these steps will not help our country. This will aggravate the situation. Sir, I do not want to deal with the economic situation. My leader, Comrade Samar Mukherjee dealt those points at length. I want to confine to some other points.

Sir, one of the most important issues that our country is facing, as I said earlier, is the unity of the people. The Government admits that the whole atmosphere in our country is being vitiated by the communal propaganda and the communal forces. Many communal riots have also taken place in our country. How to combat this? How to bring the unity of the people? How to combat the communal forces? I earnestly ask the Congress(I) colleagues whether the policies they pursue in Kerala will help in combating the communal forces, in bringing the unity of the people. In Kerala, the Congress(I) Party has allied with all caste and communal parties. They have not only made alliance with the Muslim League, but they also reached understanding with B.J.P.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): You are deviating from-the fact. Your party also had alliance with the Muslim League.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: Of course, we corrected our mistakes. I am asking your whether the Congress(I) Party has the courage to correct their mistakes. They should sever their relations with all caste and communal politics.

Sir, in the Presidential Address, it is not there as to what stand the Congress (I) intends to take on the Babri Masjid-Ramjanmaphumi issue Of course, the President's Address states that they stand for maintaining the *status quo* in regard to other places of worship. In regard to Ramjanambhumi-Board Masjid issue, it states that they stand for a negotiated settlement.

Of course, we are all for that. If negotiated settlement is not possible then what is the course of action? Has the Congress(I) gone back from their earlier stand that if no negotiated settlement is possible this matter will be referred for the Court verdict?

The other question facing us is, how to protect the unity and integrity of our country. Now, we are facing a very serious problem in Punjab. It is stated in the President's Aldress that the Congress(I) Party, the Central Government, stands by the Rajiv-Longowal Accord. Will merely stating this thing make any change in the situation? They have been saying this thing for the last so many years. Who prevented them from implementing the Rajiv-Longowal Accord? Now, the whole situation has changed. Merely stating this thing will not do any good. They have to take some bold steps. How to win over the majority of the population? How to give confidence to the common people in Punjab? Some bold steps are absolutely necessary in the present context. They should immediately hand over Chandigarh to Punjab. They should refer the water dispute to the Supreme Court. They

should also take steps to refer the border dispute to a Tribunal. They should also give due status to Punjabi language. Many other steps are also necessary. Only by taking such bold steps, we will be in a position to give confidence to the common people, win over the majority of the to our side and strengthen the unity and integrity of the country. Sir, a worse situation we are facing in Kashmir. Actually, the Central Government wants to shirk its responsibility. It was 40 years ago when the Kashmiri people cast their lot with us, thinking that they can make progress, they can keep their cultural identity. It was during the 40 years rule of Cogress(I) that a considerable section of the people in Kashmir got alienated from the mainstream of our country. There also some bold steps are necessary. We should unhesitatingly accept their special status. We should give all sorts of help for their economic progress. Then only we will be able to bring the masses with us.

In Assam, the bankruptcy of the Government is exposed. Of course, we are all for bringing the terrorists to the mainstream of our country. But what has the Government done in the case of Assam? They have set free 700 ULFA terrorists. Many of them are involved in very serious cases. The Government did not try to get any assurance from them that they will abandon terrorism and they will try to help in destoring the democratic process in our country. Without that they have set them free. Not only this, the Government did not have any consultation with the major political parties in our country. They speak about consensus. How is the consensus being evolved? It can able done only by initiating dialogue, especially on these major political issues. But no discussion was held. The Congress-I is behaving as in the past. But the situation in our country has changed. It is only by purposeful dialogue that we should be able to solve these important issues.

The President's Address mentioned about the growing cult of violence in the country. I want to ask one thing. How can the Congress-I party give such sermons when they themselves are involved in these acts of violence? In Tripuda, all major opposition parties, including my party, had to withdraw from elections. The atmosphere was not at all conducive for a free and fair election there. Above all that, what the Congress party has done now is, they have made Mr. Santosh Mohan Deb as the Central Minister. This record of the Congress party will not help in bringing a consensus in the country. In Kerala, Sir, Congress-I attack is continuing....

SHRI M. M. JACOB: What we hear is the reverse in Kerala.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: No, Sir. What is happening there appears in the papers.

The President's Address does not speak about Centre-State relations. This is a most important issue in the present context. Only by strengthening the federal democratic structure in our country we can keep our country united. Without strong States, there cannot be a strong Centre. What happened to Sarkaria Commission? We should take steps to protect the rights of the ethnic people, to protect the rights of the tribals. We should help them in fulfilling their aspirations about their economic progress, to keep their cultural identity. A fresh restructuring of the Centre-State relations is absolutely necessary in the present context.

What happened to the decentralisation policy? Nothing is mentioned in the President's Address. Two years back, Congress-I Government came up with the gimmick of decentralisation. We the opposition parties exposed this gimmick. In the name of decentralisation, they brought centralisation. Only in opposition-auled States, genuine decentdalisation was introduced. In the present economic crisis and other crisis, it is absolutely necessary to bring people nearer to power or to bring power nearer to the people. We can rely people for developmental activities, get their help for Social Welfare. We can activities. The shining example in Kerala is the literacy programme. Thousands and thousands of people co-operated and

participatel and that is why we made a tremendous success in that programme.

Of course, the President's Address spelt out the foreign policy briefly but I am sorry to say that the President in his Address made only some cursory remarks about the non-alignment policy. This has got more relevance in the present context Some said that this non-alignment policy was evolved in a particular circumstance in a bipolar world as a middle line. I don't agree with this. This has the heritage of anti-imperalism. This has heritage of national liberation struggle. Not only this, the hopes and aspirations of the Third World countries are inherent in the non-aligned movement. Now, the whole world situation has changed After the Gulf War, after the reverses in the socialist world. American imperialism is trying to impose its new world order. They intervened in Ethiopia. It caused the fall of the Ethiopian Government. They gave all sorts of help to the fundamentalists in Algeria. They are exerting all sorts of pressure in Mozambique. They are exerting all sorts of pressure on Angola forcing them to come to some sort of an agreement with the imperialist-backed UNITA. Now, India is their prime target. In this, we should take up the challenge. Our country is the second largest, next only to China in regard to population. We should take the lead Then only, our freedom can be protected. But the steps which the Central Government is taking by allowing the multi-national forces to creep in, succumbing to the pressures of modern imperialism, no doubt, would strengthen the hands of imperialism to exert more pressure on our country. So, the Government should withdraw such steps. Then only, our country's freedom can be protected. As the second largest nation next to China, we should mobilise the Third World countries against these imperialistic pressures.

Sir, I want to add one more issue. The present election has, once again, brought in the need for electoral reforms. The use of terror, money, muscle power was unprecedented during the last election. The President's Address did not mention these things, nor did the Address mention about the necessity of keeping the office of the Chief Election Commissioner out of controversy. How to curb money power, muscle power and rigging? We should think about introducing the proportional representation system. The Government should take the intiative for a purposeful dialogue on this particular issue. I am disappointed by the Address of the President. I conclude. Thank you.

SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL (Uttar Pradesh): I have a point of order Yesterday, we were sitting till 10 o'clock in the night. The hon. Finance Minister gave the reply. Only, five to six Members were present. Not a single line of the Minister's rely was published in the newspapers. I think, whatever the Members are speaking in the House should be made known to the whole nation. It is also very important. If we speak and if quorum is not there, I do not think it is useful for the country or for the Parliament. Let us see whether quorum is there. If quorum is not there, I request you to adjourn the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Regarding your point of order, a few minutes ago, we tried to take the sense of the House, and it was decided that we will continue today up to 8 p.m. Yesterday, it was an extraordinary situation. Generally, we do not sit so late. But if situations compel us, in such unavoidable situations, we extend our sitting up to 8 p.m. or up to 10 p.m.

So far as the question of quorum is concerned, if Members insist on quorum, that is a different matter. If we go by convention,....

SHRIMATI PRATIBHA SINGH (Bihar): Sir, we must go by convention.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): But you try to be brief.

SHRIMATI PRATIBHA SINGH: I will try. But I rarely speak. Therefore, Sir, I hope you will be kind to me.

उपसभाध्यक्ष महोदय, 21 मई का दिन एक भयंकर दुर्घटना था। श्री राजीव गांधी की जघन्य हत्या से देश शोक में डूब गया। इस विषय में मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं। सब से पहले मैं यह पूछना चाहती हूं कि समय रहते सूचना क्यों नहीं मिलती है ? हम ने खुफिया विभाग को इतनी बड़ी हिंसा की योजना का पता क्यों नहीं चला ? आपने इंडिया टुडे के 15 जुलाई के अंक को पढ़ा होगा। उसमें इसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। यह क्या प्रदर्शित करता है ? छः महीने से मद्रास में योजनाबद्ध काम हो रहा था। यहां तक कि विशेष प्रकार का बेल्ट बना। बम बना, मारने के तरीके का रिहर्सल हुआ। फिर भी सूचना नहीं मिली। पेरिस के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी --

> *Video footage shows lapses in security.*
>
> The only known video recording of the most wanted Sivarasan, footage of the May 8 rally, which was just a fortnight before the squad assassinated Rajiv Gandhi at Sriperumbudur, shows the one-eyed Jack in the front row Press enclosure, barely five to six metres from the dais from where Mr. V. P. Singh and other Janata Dal leaders were addressing the crowd."

ऐसी परिस्थिति में इंटेलिजेन्स विभाग क्या कर रहा था ? सी० बी०आई०, सी०आई० डी० और रा, न जाने कितने तरह के विभाग हैं तो इन्फारमेशन कलेक्ट करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई खबर नहीं मिली। आदरणीय इंदिरा जी की हत्या हुई, पूर्व सूचना नहीं मिली। अभी मुझसे पूर्व श्री सोमपाल जी फारेन एक्सचेंज की बात कर रहे थे मैं सिर्फ एक सेन्टेंस कहना चाहती हूं इंदिरा जी की मृत्यु के समय हमारा फारेन एक्सचेंज क्या था, इसकी राशि को वे देख लें। गृह मंत्रालय से आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि इन सभी विभागों के काम करने के तरीके में कहीं पर तो कमी है, भूल है। विभागों के कर्मचारी यदि सजग और सचेष्ट रहते तो क्या ये दोनों महान नेताओं की हत्या हो सकती थी ? दोनों ही बहुत सशक्त नेता थे। भारत को तेजी से प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे थे। संसार के प्रगतिशील देशों की बराबरी में भारत को ला रहे थे। आज हम संकट में है जिसकी आज शिकायत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में बाद में घटना की समीक्षा तो सरकार करेगी, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि इसकी पूर्व सूचना क्यों नहीं मिली, इसकी जांच की जाय और इन खुफिया विभागों को रिस्ट्रक्चर किया जाय। इनके अफसरों की नियुक्ति पूरी जांच पड़ताल के बाद की जाय। इन विभागों में इतनी बड़ी फौज है और हिन्दुस्तान और इन्टरपोल से उनका रिलेशन है। इन सब विभागों की इतनी बड़ी फौज के बावजूद न नेताओं की हत्या रूकी और न ही टैरोरिस्ट मूवमेंट काबू में रहा है। इसलिए गृह मंत्रालय को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक चीज की ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जिस दिन राजीव गांधी का फ्यूनरल हुआ उस दिन विदेशों के बड़े-नेता यहां आये थे। श्री यासर अराफात ने जो कि पी०एल० ओ० के प्रधान हैं, यहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं से भी कहा था कि एक महीने पहले उन्हें यह जानकारी मिली थी और उन्होंने अपने भारत स्थित राजदूत को कहा था कि वे इसकी जानकारी भारत सरकार को दे दें। किसको यह जानकारी मिली, उस पर क्या ऐक्शन हुआ, क्या बचाव का कार्यक्रम हुआ, इस पर रोशनी डालने की जरूरत है।

पिछली सरकार ने श्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में जांच के लिये न्यायमूर्ति श्री जे०एस० वर्मा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया है। इसको 21 जुलाई को दो महीने पूरे हो जायेंगे किन्तु अभी तक टर्म्स आफ रेफरेंस तैयार नहीं हुए ? अभी तक कोई सेक्रेटरी अप्वाइंट नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। समय के साथ जो सबूत

होते हैं वे धीरे-धीरे मिटने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि कौन जानकारी देकर झमेले में फंसने जाये। इसलिये इतनी बड़ी जघन्य हत्या के मामले में सरकार से इस मामले में रफ्तार तेज करने का मेरा आग्रह है। आपके माध्यम से सरकार से मेरा कहना है कि इस मामले की जांच में बड़ी मुस्तैदी की अपेक्षा भारत की जनता कर रही है क्योंकि राजीव गांधी सिर्फ हम कांग्रेस जनों के नेता ही नहीं थे बल्कि सारे संसार के डेवलपिंग और अंडर-डेवलप्ड देशों के नेता भी थे। उनकी निर्मम हत्या ने हम सबको शोक सागर में डुबो दिया है। वे हर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता के दिल के महबूब थे और इसीलिये हमारे अंदर बेचैनी है कि पूर्व सूचना क्यों नहीं मिली ? अब तो हम अपने नेता को वापस तो नहीं ला सकते हैं।

महोदय, राष्ट्रपति जी ने कहा है कि सरकार राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों समुदायों की भावनाओं का समुचित आदर करते हुए बातचीत द्वारा हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि दोनों ही समुदाय को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। राम शब्द की उत्पत्ति, उसका रूट क्या है ? वी०एस० आप्टे की डिक्शनरी, (शब्दकोष) में "रम" संस्कृत शब्द का अर्थ है खेलना-टू प्ले, आनंदित रहना-टू बी प्लीज्ड और डिलाइटेड, प्रसन्नता का मत्रा रिज्वाइस इत्यादि। राम शब्द द्योतक है आनन्द, प्रसन्नता, अति सुन्दर, मधुर आदि का। ऐसे राम क्या संघर्ष से बनाए भवन में रहेंगे ? जहां भी सद्भावना है, मानव का मानव से प्रेम है, वहीं राम है और जहां राम है वहीं अयोध्या है। मंदिर तो सिर्फ ईंट और पत्थरों का एक भवन होगा पर असल में राम की वहां उपस्थिति आवश्यक है।

वैसे ही खुदा, रहीम कैसे उस मकान में रहेंगे जहां कलह, संघर्ष और मनुष्य मनुष्य का खून बहायेगा। जो भी सच्चा राम भक्त होगा वह कभी भी अपने राम का मंदिर घृणा, द्वेष के पत्थर और खून की नदी बहाकर नहीं करेगा और वैसे ही सच्चा मुसलमान अपने खुदा का महल नफरत और हिंसा पर नहीं चाहेगा। लेकिन जब से धर्म का राजनैतिक फायदे के लिए उपयोग करना शुरू हुआ तब से ऐसी स्थिति बनी है कि धर्म कहां गया इसका कोई पता नहीं है। हमारे हाथ धर्म के नाम पर सिर्फ ढकोसला रह गया है। और हम धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर अब कम्युनलिज्म साम्प्रदायिकतावाद की ओर बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसका कोई अंत नहीं है ?

अयोध्या तो तभी असली अयोध्या होगी जब राम और रहीम दोनों के सुन्दर भवन वहां होंगे और दोनों समुदाय के लोग अयोध्या में प्यार, सद्भावना और एकता की गंगा बहायेंगे। कम से कम मैं अपने राम की यही कल्पना करती हूं। अमरनाथ के सिद्ध स्थान की पूजा का आज भी एक हिस्सा एक मुसलमान परिवार को जाता है वैसे ही क्या सूफी संतों को हिन्दु श्रद्धा से ही नहीं देखते हैं ? हजारों वर्षों से हिन्दु और मुसलमान संग रहे हैं किन्तु राजनीति में फायदा उठाने के लिए चंद नेताओं ने झगड़ा बरपा है। आम हिन्दु, मुसलामान झगड़ा नहीं चाहते हैं। अतः सरकार से निवेदन है कि ऐसा माहोल तैयार किया जाए कि अयोध्या सुन्दरता, प्यार, आनन्द की एक प्रतीक हो। दो ही तरीके हैं या तो आपसी बातचीत से जन्म भूमि का मामला तय हो या ज्यूडिशियल प्रोसेस से तय किया जाए। तीसरा तो कोई रास्ता नहीं नजर आता है। पहला रास्ता तो आपसी बातचीत का दोनों धर्मों में सद्-भावना लाने में अधिक फायदेमंद होगा। अतः सरकार से यह प्रार्थना है कि सरकार ऐसा माहोल तैयार करे कि दोनों समुदाय जिद छोड़कर इस मामले को तय कर लें। (समय की घंटी) अभी मुझे बच्चों और महिलाओं के विषय में कुछ कहना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम०ए० बेबी) : जल्दी खत्म कीजिये।

श्रीमती प्रभा सिंह : राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस दशक की समाप्ति के पहले प्रत्येक गांव में टेलीफोन अवश्य पहुंचे जायें । यहां पर मैं सरकार से आपके द्वारा कहना चाहती हूं कि आज जब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो हमें क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी पर जोर देना चाहिए ताकि जो खर्च करें वह रिजल्ट ओरियेंटेड हो । बिहार की राजधानी पटना तक में तो टेलीफोन काम करता ही नहीं । कहने को जिला और सब डिविजन में टेलीफोन की मशीन है किन्तु बात नहीं हो सकती है । मेरा इतना ही कहना है कि जो सरकार कहे वह कर सके । जैसे आज नीतियों में उद्योग, व्यापार आदि में परिवर्तन की बात सोच रहे हैं, वैसे ही आज क्वालिटी की बात सोचने की आवश्यकता है । प्रायर्टीज को अधिक गम्भीरता से तय करने की आवश्यकता है । विशेषकर जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात सोचते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के इलावा उत्पादक रोजगार के अवसरों में शीघ्रता से वृद्धि का हमारी योजना और आर्थिक नीति का लक्ष्य है मेरा कहना है कि यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कौन-कौन से हो सकते हैं इसकी शैक्षिक व्यवस्था ट्रेनिंग प्रोग्राम वहां के उपस्थित सर्कमस्टांसेज के मुताबिक कर सकें और अधिक से अधिक सेल्फ इम्पलायमेंट के अवसर दे सकें । पर इसके लिए सड़क और बिजली आवश्यक हैं । अगर यह दोनों गांव में नहीं जाते हैं तो कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, महिलाओं और बच्चों की मदद सरकार करना चाहती है तो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी इंडस्ट्रीज में इम्पलायमेंट की बाबत जो कानून है विशेषकर केमिकल इंडस्ट्रीज में उनको सख्ती से लागू करें । वेगरेंट बच्चों को काम सिखाने के लिए संस्थाओं को अधिक से अधिक मदद देनी चाहिए । बहुत से बच्चे पढ़ाई में दिल नहीं लगाते हैं किन्तु यदि ऐसे बच्चों को कोई काम सिखाया जाता है तो अच्छा काम करते हैं । बाल सहयोग एक ऐसी संस्था है दिल्ली में जो यहां पर इस तरह की शिक्षा देती है । इस संस्था की स्थापना भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने की थी । यदि सरकार थोड़ी सी मदद इस संस्था को दे तो वेगरेंट बच्चों के जीवन में एक नई आशा और नई प्रेरणा का संचार होगा । यह आदर्श बन सकता है और प्रदेशों में भी हम ऐसी संस्थायें खोल सकते हैं । राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा है कि आरक्षण का लाभ आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को भी दिया जाए जो विद्यमान योजनाओं के दायरे में नहीं आते हैं और पिछड़े वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाएगी । मैं माननीया सदस्या श्रीमती जयंती नटराजन के साथ सहमत हूं कि जब तक पिछड़े वर्ग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश की प्रगति सम्भव नहीं है । देश आगे नहीं बढ़ सकता है । उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहती हूं लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि बिहार और तमिलनाडु की सामाजिक परिस्थिति बिलकुल भिन्न रही । इसलिए जितना आक्रोश ब्राह्मण और नान-ब्राह्मण में तमिलनाडु में है उतना बिहार में नहीं है । इस का कारण थोड़ा ऐतिहासिक है । इसका कारण है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का कार्यक्षेत्र बिहार रहा है । इन दोनों लोगों ने कर्मकांड और जातिभेद का विशेष विरोध किया । इन्होंने कोशिश की कि कर्मकांड का ढकोसला भी हट जाए हिन्दु जाति से जातिभेद भी हट जाए । इन लोगों ने एक जाति मानी जो मनुष्य जाति थी । इसलिए न बुद्धिज्म में कोई जाति है और न जैनिज्म में कोई जाति है । बुद्धिज्म और जैनिज्म का बिहार के समाज पर बहुत गहरा असर है । इस शताब्दी में भी बिहार में त्रिवेणी संघ नामक एक संस्था थी जिसका उद्देश्य था पिछड़ी जाति का उत्थान । उस समय की राजनीति में रहने वाले जो लोग थे, सर गणेष दत्त सिंह, सी०पी० एन० सिंह तथा डा० श्रीकृष्ण सिंह जो बाद में बिहार के मुख्य मंत्री हुए, सभी ने त्रिवेणी संघ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया । बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट

8 P.M.

बोर्ड था। सामाजिक न्याय देने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, जैसे ही उस समय कांग्रेस सरकार आई, जमींदारी एबालिशन किया, लैंड सीलिंग बिल पास किया। कर्पूरी जी के समय में आरक्षण पर पुनः विचार हुआ और परसेंटेज बढ़ाया गया लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please conclude.

श्रीमती प्रतिभा सिंह : सिर्फ दो मिनट बस। लेकिन वी०पी० सिंह सरकार ने आरक्षण का मुद्दा कुछ ऐसे ढंग से पेश किया कि वह संघर्ष की राजनीति बनी। उनकी कैबिनेट के सदस्य सड़कों पर जाति-भेद का नाम लेकर खून की नदी बहाने की बात करने लगे। पिछड़े वर्ग के फायदे की बात सिर्फ कल्पना में रह गई और रह गई केवल द्वेष, नफरत की राजनीति। जब जनता ने महसूस किया कि यह राजनीति है तो जनता दल का क्या हश्र हुआ वह सबके सामने है। यह और बातें हैं कि बिहार से ही जनता दल के काफी लोग आये हैं, किन्तु वहां चुनाव फार्स था। मैं वहां के चुनाव के बारे में यहां दोहराना नहीं चाहती हूं क्योंकि समय की कमी है। आज यशवंत सिन्हा जी ने काफी कुछ बताया है।

वी०पी० सिंह की सरकार का मकसद केवल गांव-गांव में नफरत फैलाना था। यह चीज जनता को पसंद नहीं थी और जनता ने समझा कि तीन-चार हजार जातियों का नाम और आंकड़ों के अलावा कितने लोगों को केन्द्र में इस स्कीम के अंदर नौकरी मिली। कितनों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। ये सारे प्रश्न उठे। कितनों को विद्यालयों में पढ़ने की सुविधा मिली। ये सारे प्रश्न उठे।

किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए पहले माहोल बनाना होता है तब कानून के द्वारा उसे व्यवस्थित रूप देना होता है। उदाहरण के लिए कांग्रेस ने ही हिंदू कोड बिल द्वारा महिलाओं को अधिकार दिया तो समाज ने स्वीकार किया वैसे ही कांग्रेस ही पिछड़े वर्ग, हरिजन और आदिवासियों को सामाजिक परिवर्तन तथा कानून द्वारा मजबूत करेगी ताकि हमारा देश गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी और अंत में राजीव जी के स्वप्नों को पूरा कर शक्तिशाली देशों की पंक्ति में खड़ा होकर आगे बढ़े। सामाजिक न्याय कांग्रेस का शुरू से ही ध्येय रहा है और आगे भी रहेगा चूंकि उन्होंने इस तरह की नीतियों को आगे बढ़ाया है। सरकार सभी प्रयत्नों के लिए कटिबद्ध है और इसमें मुझे पूर्ण आशा है कि विरोधी दल के लोग भी पूरी तरह से साथ देंगे। क्यों? इसलिए कि पिछड़े वर्ग का उत्थान केवल राजनीतिक फायदे के लिए न हो बल्कि हकीकत में देश को आगे बढ़ाने के लिए हो।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : 40 साल में आपने आगे बढ़ाया? नहीं बढ़ाया है।

श्रीमती प्रतिभा सिंह : हां बढ़ाया है। तामिलनाडु में बढ़ा है, महाराष्ट्र में बढ़ा है। मैं पिछड़े वर्ग की बात कर रही हूं... (**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : आप जो पिछड़े वर्ग की बात कर रही हैं मैं आपको बता दूं.. (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please don't enter into an argument. Please conclude.

मैं **श्रीमती प्रतिभा सिंह** : इसके साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करती हूं। आपने क्या किया डेढ़ वर्ष में ... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : हमने डेढ़ वर्ष में कुछ नहीं किया लेकिन आपने 40 वर्ष में क्या किया ... (**व्यवधान**)

श्रीमती प्रतिभा सिंह : आपने कुछ नहीं किया। बताइये कितने लोगों को नौकरी दी? बताइये कितने लोगों की

[श्रीमती प्रतिभा सिंह]

आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हुआ ? कांग्रेस के समय में हुआ। पर कांग्रेस ने इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहा।... (व्यवधान)

THE VICE CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Kumari Chandrika Kenia. The last speaker.

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA (Maharashtra): I hope I will get sufficient time. Otherwise I will speak tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You may speak.

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: Will you give me sufficient time?.... (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You may take eight minutes (*Interruptions*).

Let our honourable sister speak.

श्री नोहम्मद अफजल उर्फ मीम-अफजल : मैं दर्खास्त करूंगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। हम लोग चले जाते हैं, या तो कोरम होना चाहिए सुनने वाले लोग होने चाहियें। हमें तो समझ में यह बात नहीं आती। न वह अखबारों तक पहुंचता है, न टी०वी० और न रेडियो वाले देते हैं।

आखिर यहां जो लोग बात करते हैं, वह देश तक जानी चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया है। कल फाइनेंस मिनिस्टर ने जो यहां जवाब दिया है, मुझे अफसोस है यह बात कहते हुए कि बहुत सारे लोगों ने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन मांगा और उनका जवाब सुने बगैर चले गये। उनको इतना इंट्रेस्ट तो होना चाहिए कम से कम कि वह जवाब सुनें और यह देश में जाना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या जवाब दिया है, या यहां जो लोग बैठते हैं, वह क्या कहना चाहते हैं। पर न तो उसको रेडियो देता है और न ही टी०वी० देता है। आज सुबह किसी का कोई जिक्र नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर की एक लाईन नहीं छपी है।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रेस के लोग भी रात में दस बजे तक बैठते हैं। हम लोग सीधे घर चले जाते हैं और उन लोगों को ग्यारह बजे तक अपनी रिपोर्ट देनी होती है और अखबारों तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो मैं इनसिस्ट करूंगा कि या तो कोरम पूरा हो... (व्यवधान)

†[شری محمد افضل عرف م - افضل : میں درخواست کرونگا کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ چلے جاتے ہیں - یا تو کورم ہونا چاہئیے یا سننے والے لوگ ہونا چاہئیے - ہمیں تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی - نہ وہ اخباروں تک پہونچتا ہے نہ ٹی - وی اور نہ ریڈیو والے دیتے ہیں -

آخر یہاں جو لوگ بات کرتے ہیں - وہ دیش تک جانی چاہئیے - میں آپکو اداہرن دیا ہے - کل فائیناینس منسٹر نے جو یہاں جواب دیا ہے - مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ بہت سارے لوگوں نے فائیناینس منسٹر صاحب سے کلیریفیکیشن مانگا اور جواب سنے بغیر چلے گئے - انکو اتنا انٹرسٹ تو ہونا چاہئیے کم سے کم کہ وہ جواب سنیں اور یہ دیش میں جانا چاہئیے کہ فائیناینس منسٹر نے کیا جواب دیا ہے - یا یہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں - پر نہ تو اسکو ریڈیو دیتا ہے - اور

نہ ہی تو - وہ دیکھا ہے - آج صبح کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے - فائیڈینس سلسٹم کی ایک لائن نہیں چھپی ہے - میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریس کے لوگ بھی رات میں دس بجے تک بیٹھتے ہیں - ہم لوگ سیدھے گھر چلے جاتے ہیں - اور ان لوگوں کو گیارہ بجے تک اپنی رپورٹ دینی ہوتی اور اخباروں تک پہونچ ہی نہیں پاتی ہے - تو میں انسسٹ کرونگا کہ یا تو کورم پورا ہو۔ (مداخلت)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Your point is well taken. As I have already mentioned, we will try to conclude...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : आपकी पार्टी ..... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, रत्नाकर पाण्डेय जी, हम सब की कलेक्टिव रेस्पांसिविलिटी है ।

†[شری محمد افضل عرف م - میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں - وقد کر پانڈے جی ہم سب کی کلیکٹیو ریسپانسیبلٹی ہے -]

डा० रत्नाकर पाण्डेय : हम लोग तो जब ताला बंद हो जाता है, तब जाते हैं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: जो बैठे हुए हैं, या जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं । हमारे मैम्बर्ज को पता लगना चाहिए कि अगर आज कोरम पूरा न होने की वजह से हाऊस एजर्न होता है, तो कल हमारे लोग इसका ख्याल रखेंगे । . . . (व्यवधान)

†[شری محمد افضل عرف م - افضل: جو بیٹھے ہوئے یا جاتے ہیں - میں انکی بات نہیں کر رہا ہوں - ہمارے ممبرز کو پتہ لگنا چاہئے - کہ اگر آج ہاؤس کورم پورا نہ ہونے کی وجہ ہاؤس ایڈجرن ہوتا ہے تو کل وہ لوگ اسکا خیال رکھیں گے - . . . . (مداخلت) . .]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please do not further prolong the preceedings. We will consider..

कुमारी चन्द्रिका प्रेमजी केनिया : महोदय, अगर यह सवाल मुझसे पूछा जाए कि भारत की कौनसी बात से आपको लगाव है और कौनसी बात पर आपको ज्यादा विश्वास है, तो मैं इस सवाल का जवाब इस तरह से दूंगी कि भारत की जनता से मुझे लगाव है, भारत की जनता पर मुझे विश्वास है और एक अछूती सी बात भारत की जनता में है, एक अलग सी बात है और वह है भारतीयता उनमें कूट-कूट करके भरी हुई है । भारतीयपन उनमें भरा हुआ है और भारत की संस्कृति की नींव हमारे भारत की जनता है और मैं तो समझती हूं कि भारत की सबसे बड़ी सम्पत्ति, भारत का सबसे बड़ा खजाना मानव सम्पत्ति का है और यह बड़े अफसोस की बात है कि हम इस मानव सम्पत्ति का सही-सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है और भरपूर फायदा उठा नहीं पा रहे हैं; चाहे वह राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वह सरकार के माध्यम से हो ।

†Transliteration in Arabic Script.

[कुमारी चन्द्रिका प्रेमी केनियाजी]

महोदय, हमें चाहिए कि हम ऐसी नीतियां बनायें, ऐसे नियम कायम करें और ऐसे कानून आविष्कार करें जो लोगों से जुड़े हों, जो अवाम की भलाई के लिए हों और भारत की जनता को मैं बार-बार अभिवादन करना चाहूंगी, बार-बार सलाम करना चाहूंगी, क्योंकि भारत की जनता ने फिर एक बार अपना विश्वास लोकशाही की प्रणाली से जाहिर किया है और राजनयिकों को जो बहुत दफा खलनायक की भूमिका अख्तियार कर लेते हैं, जब वोट बैंक की तलाश में वह निकलते हैं, उनको आगाह कर दिया है, उनको चेतावनी दे दी है और उनको कहा है कि वह मनमानी नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें सरकार चलानी है, तो सही ढंग से सरकार चले। लोगों की जो आशायें-आकांक्षायें हैं, उनको परिपूर्ण करने के लिए सरकार चलायें, काम करने वाली सरकार दें। तभी जनता उनका सहकार करेंगी, तभी जाकर जनता उनका साथ देगी, वरना उनको सरकार से हटाया जाएगा।

वह बात बड़ी स्पष्ट हो गई है। जब हम पिछले चुनाव की ओर दृष्टि करते हैं, तो फिर एक दफे यह बात भारत की जनता ने साबित करके दिखाया है कि लोकशाही का मतलब लोगों से बनी हुई सरकार हो, लोगों के लिए सरकार हो और लोगों की सरकार हो।

"Government of the people, for the people and by the people."

यह बात उन्होंने जाहिर की है और इसके लिए सत्ता में बागडोर थामे हुए राजकर्मियों को अवाम तक पहुंचना होगा, लोगों की धड़कनों की पहचान करनी होगी। महात्मा गांधी की महानता और खूबी यही थी कि उन्होंने जनता की नाड़ी की धड़कन को पहचाना हुआ था और स्वामी विवेकानन्द ने भी यही किया था—
"Serve the living God, serve tre down-trodden, nedy anl the poor the weak."

सरकार पिछड़े हुए लोगों की हो, अवाम की हो, दीन-दुखियों की हो। पर यह बड़े दुख और खेद की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि सरकार और जनता में फासला दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है और उसकी गुनाहगार है हमारी नौकरशाही की प्रणाली, हमारी नौकरशाही की प्रथा। नौकरशाही को चाहिए था कि वह जनता और सरकार के बीच में एक सेतु बन जायें, कड़ी बन जायें, लिंक बन जाये, एक ब्रिज बन जाए। पर वह काम वह नहीं कर पाये हैं। चाहे वह आइवरी टावर्ज में बैठकर काम करते हों, चाहे एयर-कंडीशंड रूम में बैठें कर नीतियां बनाते हों, सरकार और जनता के बीच यह फासला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। हमें चाहिए कि हम गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली में ऐसी समितियां बनाएं जहां पर लोक प्रतिनिधि हों, जो जनता के रोज़-ब-रोज़ के मसलों की ओर ध्यान दें, उनके जो रोज़ के सवालात हैं उनके ऊपर ख्याल करें और उनके सुख-दुख के साथी बनें। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में महिलाओं के उत्थान के बारे में जिक्र हुआ है मगर मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि जिस बात को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। वह राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी कहीं आखिर में उल्लेख आता है, उसका कहीं जिक्र आता है। जब हम यह देखते हैं, कल्पना करते हैं, ख्याल करते हैं कि 50 प्रतिशत आबादी हमारी महिलाओं की है तो उनकी जो उपेक्षा होती है वह उपेक्षा बहुत ही गलत है। सिर्फ नेशनल कमीशन फार विमेन बनाने से काम तमाम नहीं हो पाता, यह तो सिर्फ नाम के वास्ते कदम उठाने की बात हो गई है। हमें तो महिलाओं को जो समाज में दूसरे दर्जे का स्थान दिया गया है उसको मिटाना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने कहा था :

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

तो नारी को यह जो अबला कहा गया है वह उनकी जो एक कमजोरी है, उनकी जो एक पिछड़ेपन की अवदशा है, उसको हमें दूर करना होगा, उसको मिटाना

होगा, उसके लिए हमें काम के अवसर प्रदान करने होंगे, उनको आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करनी होगी, उनके लिए स्वरोजगार की योजनाएं हमें बनानी होंगी और शिक्षा के साधन उनके लिए उपलब्ध कराने पड़ेंगे । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगी कि शिक्षा मंत्री के रूप में मैंने महाराष्ट्र में काम किया है और मुझे देहातों और गांवों में भी जाने का मौका मिला हैं । मुझे यह पता चला खास करके कि गांवों में महिलाएं स्कूल तक भी जा नहीं जाती हैं । इसके लिए कारण यह भी है कि बहुत फासले पर, दूर-दराज में स्कूल लगते हैं और जहां को-एजुकेशन का वातावरण रहता है, माहौल रहता है वहां महिलाएं या बच्चियां पढ़ाई के लिए नहीं जाती हैं । तो यह आवश्यक बात होगी कि हम महिलाओं के लिए, खास तौर पर महिलाओं के लिए, सिर्फ उनके लिए ही शिक्षा के साधन उपलब्ध कराएं, स्कूल और कालेज उनके लिए लगाएं ।

पंचायती राज का कानून बनाया गया । राजीव जी की सरकार ने यह कदम उठाया था ताकि लोगों तक न सिर्फ हम सत्ता पहुंचाएं, लोगों तक हम राशि और धन की उपलब्धि भी प्राप्त करा सकें । उसमें भी यह प्रयोजन किया गया था कि 30 प्रतिशत हम आरक्षण महिलाओं के लिए रखें ताकि पंचायती राज के माध्यम से ग्राम पंचायत और जिला परिषद् में काम करने का अवसर उनको मिले । लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि क्या महिलाएं इतनी कम का बलियत हासिल किए हुए हैं कि वे सिर्फ पंचायती राज के माध्यम से ग्राम पंचायत और जिला परिषद् तक मैं ही काम कर सकती हैं ? क्या उनकी का बलियत और क्षमता इतनी नहीं है कि वे कार्पोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट में आएं ? आप यहां पर नजर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि महिलाओं की संख्या चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे असेंबली में हो दिन-ब-दिन कम होती जाती है । इसलिए हमें यह जो एक अन्याय है, असमानता की भावना है, उसको दूर करना होगा और महिलाओं के लिए कार्पोरेशन, असेंबली और पार्लियामेंट में 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व उनको देना होगा । महोदय, समाज के रथ के दो पहिए स्त्री और पुरुष हैं । उनमें से अगर एक पहिया पिछड़ा हुआ रह जाता है, पीछे रह जाता है, उस गति के हिसाब से नहीं चलता है तो मैं समझती हूं कि पूरा समाज पिछड़ा हुआ रह जाता है, पूरा समाज विकास से वंचित हो जाता है । इसलिए हमें स्त्री को अपने आप में खुद्दार, स्वाभिमानी और आधुनिक जीवन की हकदार बनाना है और उसके लिए ऐसे हालात और संयोग का हमें आविष्कार करना है ताकि भारतीय नारी बड़े गर्व के साथ कह सके कि,

"खुदी को कर बुलन्द इतना कि तकदीर से पहले,

खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ।"

भारतीय नारी अपना नसीब, अपनी तकदीर अपने हाथ से बनाए, यह माहौल हमें पैदा करना होगा ।

महोदय, भारत का भविष्य नौजवान पीढ़ी से जुड़ा हुआ है । मगर हमारा युवा वर्ग चिंतित है, फिक्रमंद है, परेशान है । वह अपनी जो पढ़ाई-लिखाई है, काबलियत है, क्षमता है, टेलेंट है, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है । उसे सही ढंग से व्यक्त करने का उसे रास्ता नहीं मिल रहा है । उसको मंजिल नहीं मिल रही है । यही वजह है कि वह देश की फिक्र नहीं करता है क्योंकि वह अपनी निजी समस्याओं में काफी मशगूल है और बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रश्न उसके सामने है । महोदय, दूसरी ओर पढ़े-लिखे नौजवान जो हमारे देश के काम आ सकते थे, इसके भविष्य को संवार सकते थे, विदेश में जाकर बस रहे हैं । यह बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर गौर करने की जरूरत है । ब्रेन-ड्रेन का यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है, तो क्या हम इस सिलसिले को रोक पाएंगे ? हमें रोजगार को बढ़ाना होगा, उत्पादन को बढ़ाना होगा और हरेक युवा के भविष्य को संवारना

होगा तब जाकर हम देश के भविष्य को सुनहरा बना सकेंगे । (*Time bell rings*). I need some time, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): This is not your maiden speech.

KUMARI CHANDRIKA PREMJI KENIA: I know that it is not my maiden speech.

महोदय, हिंसाचार का वातावरण पूरे देशभर में व्याप्त है । चाहे वह काश्मीर का सवाल हो, चाहे वह पंजाब का मुद्दा हो या आसाम का मसला हो, मेरा यह मानना है कि चंद गुमराह नौजवान जो कि बेकारी का शिकार है, हिंसाचार पर उतारू है और कानून और कायदे की व्यवस्था को वह हिला रहे हैं । महोदय मैंने कई बार इस सदन में काश्मीर के बारे में जो मेरे विचार हैं, ख्यालात हैं, वह यहां पर पेश किए हैं और मैं यह मानती हूं कि काश्मीर को देश की अस्मिता से जोड़ दिया जाए । उसका अलग अस्तित्व बनाए रखना, अलग प्रबंध करना न भारत के हित में है और न काश्मीर के हित में है । महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की नजर काश्मीर पर लगी हुई है और बड़े गलत अंदाज़ से वहां पर कार्यवाही हो रही है । हम पाकिस्तान को आगाह करना चाहेंगे कि काश्मीर के ऊपर से वह अपनी बंद नजर हटा ले । महोदय, पाकिस्तान में कमांडो ट्रेनिंग कैम्प लगे हुए हैं जहां कि काश्मीर के 18–18 साल की उम्र के बहुत से नौजवान भेजे जाते हैं और वहां पर उनको बंदूक चलाना, मशीनगन चलाना कत्ले आम करना सिखाया जाता है । तो इसके ऊपर हमें रोक लगानी चाहिए ।

महोदय, बहुत से जो हिन्दू परिवार हैं, वह काश्मीर को छोड़कर जम्मू, दिल्ली और अलग-अलग जगहों पर बसे हुए हैं मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि उनके जो हालात हैं, उनकी जो विवशता है उसे अपनी आंखों से देखे तो पता चले कि वह किस तरह का जीवन जी रहे हैं ? किस तरह का अमानवीय जीवन वह कैम्पस में जी रहे हैं ? इसलिए मैं नरसिंहराव जी की कांग्रेस सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि वहां उनको राशन की सुविधा नहीं है, रहने के लिए ठीक तरह से कैम्पस नहीं लगे हैं, पढ़ाई के साधन नहीं हैं । इन सब बातों पर हमारी सरकार गौर करे ।

महोदय, पंजाब के चुनाव स्थगित किए गए हैं जिससे कि लोकशाही प्रणाली पर फिर एक बार जांच आयी है । महोदय, पंजाब की जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह खुद तय करे कि किस प्रकार की सरकार उनको चाहिए । हमें फिर सोचना है ताकि पंजाब की जनता को अपना हक और अधिकार मिल सके । वह अपनी सरकार खुद चुन पाएं । यह पंजाब का मसला राजकीय स्वरूप का है और उसका हल भी राजकीय हो सकता है ।

महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मंदिर-मस्जिद विवाद के बारे में जिक्र किया है । उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त, 1947 की स्थिति बनाए रखने के लिए एक विधेयक पेश किया जाएगा । महोदय, जो सवाल भारत की अस्मिता से जुड़ा है, भारत की प्राचीन परंपरा से जुड़ा है, भारत की संस्कृति से जुड़ा है, उस सवाल का समापन, उस सवाल की इतिश्री इन शब्दों को दोहराने से नहीं हो सकती है । भारत की जनता की भावना, उनकी ऊर्मि, उनके ख्याल, उनके अस्तित्व के साथ खेलना छोड़कर हम हकीकत को नजर के सामने लाए । सांप्रदायिकता का आक्षेप लगाकर, हिन्दुओं को कमजोर बनाकर हम हिन्दुस्तान को कमजोर बना रहे हैं । यह मेरा मानना है ।

आखिरी बात, शिक्षा-पद्धति के बारे में दो शब्द कहकर मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर किए मेरे वक्तव्य को

समाप्त करना चाहूंगी । राजीव जी की सरकार ने नई शिक्षा पद्धति बनाई थी, मुझे याद है नरसिंह राव जी, जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, उस जमाने में ह्यूमन रिसोर्सेस डवलपमेंट मिनिस्टर रहा करते थे और उनकी रहबरी में यह नई शिक्षा-पद्धति बनाई गई । मैं यह कह सकती हूं कि वह खुद ही कर्ता थे, जो नई शिक्षा-पद्धति उन्होंने बनाई, और हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से वह हमारे लिए गीता बन चुकी है । रामामूर्ति कमीशन कायम किया गया जनता दल की रिजीम में, उसके बाद चन्द्रशेखर जी की सरकार ने भी यही बात दोहराई । तो मैं समझती हूं कि यह जो नई शिक्षा-पद्धति राजीव जी की सरकार ने बनाई थी, उसमें परिवर्तन लाने की बात थी, यह परिवर्तन हम स्थगित रखें और जो नई शिक्षा-पद्धति राजीव जी की सरकार ने बनाई थी, उसमें हमारी आस्था हम फिर से बरकरार करें ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगी कि नई शिक्षा-पद्धति का जहां तक सवाल है, जो प्राथमिकता शिक्षा को देनी चाहिए, वह प्राथमिकता दी नहीं जाती है । पूरे बजट की तरफ हम देखें तो पता चलता है कि शिक्षा के लिए छह प्रतिशत से भी कम राशि हम लगाते हैं । मेरा यह निवेदन रहेगा सरकार से कि छह प्रतिशत से ज्यादा राशि आप शिक्षा के लिए रखें ताकि जो विकास के रास्ते हमें शिक्षा के माध्यम से लेने हैं, वह विकास के रास्ते हम ला सकें । महाराष्ट्र का जो शिक्षा का बजट था 1000 करोड़ से भी ज्यादा का वह बजट था, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें से ज्यादा से ज्यादा खर्चा हम टीचिंग और नोन-टीचिंग स्टाफ के ऊपर ही लगाते थे और .001 परसेंट भी हम डवलपमेंट के काम पर नहीं लगा सकते थे । तो ऐसे हालात शिक्षा-पद्धति के बारे में हैं । कम से कम छह प्रतिशत राशि हमें बजट में से जरूर मुकर्रर करनी चाहिए ताकि शिक्षा का काम बढ़ सके ।

नवोदय विद्यालय के बारे में बीच में सरकार ने कहा था कि यह नवोदय विद्यालय काम की बात नहीं है । मैं जरूर यह कहना चाहूंगी कि अगर हम पिछड़े लोगों की तरफ देखना चाहते हैं, मंडल-कमीशन की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा काम हमें उनके लिए शिक्षा के रास्ते खोलने का करना पड़ेगा । यह नवोदय विद्यालय अपने आप में बहुत बड़ी बात है, उसको हमें कण्टीन्यू करना चाहिए, कायम करना चाहिए ।

मेथ्यू आरनोल्ड ने नौजवानों के लिए एक पंक्ति लिखी हुई है, वह मैं यहां दोहराना चाहूंगी और अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगी—

"For this world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, has really neither joy nor done nor life nor certifide nor peace nor help from pain, and we are here on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and fight where ignorant armies clash by might" ,

Thank you.

डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा । अगर चाहें तो सदन की राय ले लें ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): In the list your name is not on the top. Therefore, I can't help it.

The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Saturday, the 20th July, 1991.

The House then adjourned at twenty-four minutes past eight of the clock till eleven of the clock on Saturday, the 20th July, 1991.